आर्थिक समीक्षा

सत्यमेव जयते
Government of India

2023-24

मुख्य विशेषताएं

आर्थिक समीक्षा 2023-24 की मुख्य बातें

आर्थिक समीक्षा 2023-24 के दस्तावेज 'मुख्य बातें' में इस समीक्षा के तेरह अध्यायों में से प्रत्येक के मुख्य पहलुओं को अध्याय-वार संकलित करके प्रस्तुत किया गया है। इन मुख्य बातों का उल्लेख चार्ट, इन्फोग्राफिक्स, तालिकाओं के माध्यम से और पाठ के न्यूनतम उपयोग से किया गया है, जो 30-35 पृष्ठों के संक्षिप्त दस्तावेज के रूप में हैं। इस प्रकार 'मुख्य बातें' दस्तावेज आर्थिक समीक्षा को संक्षेप में प्रस्तुत करता है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। मुझे आशा है कि पाठकगण इस 'मुख्य बातें' दस्तावेज से जुड़ पाएंगे और गहन अध्ययन हेतु समीक्षा में वर्णित प्रासंगिक विषयवस्तु की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रेरित होंगे।

वी. अनंत नागेश्वरन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

विषय-सूची

1	अर्थव्यवस्था की स्थिति: निरंतर आगे बढ़ते हुए	03
2	मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: स्थिरता ही मूलमंत्र	06
3	कीमतें और मुद्रास्फीति - नियंत्रण में	08
4	बाह्य क्षेत्र: समृद्धि के बीच स्थिरता	11
5	मध्यम अवधि परिदृश्य: नए भारत के लिए विकास दृष्टि	14
6	जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण: समझौताकारी सामंजस्य	15
7	सामाजिक क्षेत्र: कल्याण जो सशक्त करे	17
8	रोजगार और कौशल विकास: गुणवत्ता की ओर	18
9	कृषि और खाद्य प्रबंधन: यदि हम सही कर लें तो कृषि में बढ़ोत्तरी अवश्य है	20
10	उद्योग: मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य	21
11	सेवाएँ: विकास के अवसरों को बढ़ावा देना	24
12	अवसंरचना: संभावित विकास को प्रोत्साहन	26
13	जलवायु परिवर्तन और भारत: हमें इस समस्या को अपने नजरिए से क्यों देखना चाहिए	28

अर्थव्यवस्था की स्थिति: निरंतर आगे बढ़ते हुए

वैश्विक आर्थिक विकास मजबूत रहा है

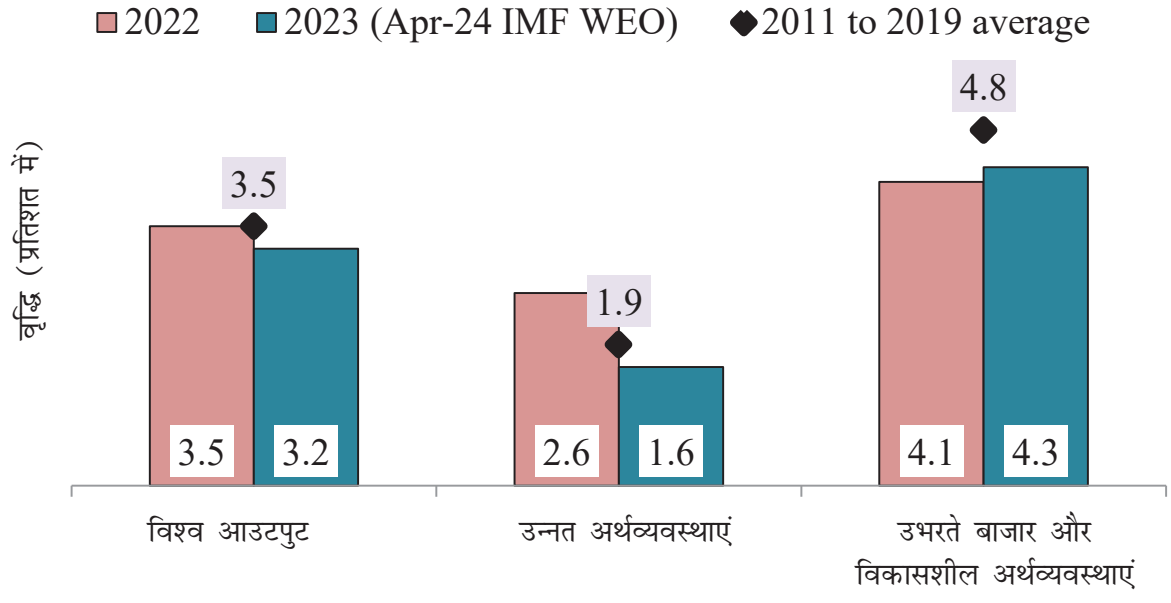

वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव कम हो रहा है, जबकि 2023 में व्यापारिक व्यापार में कमी आएगी

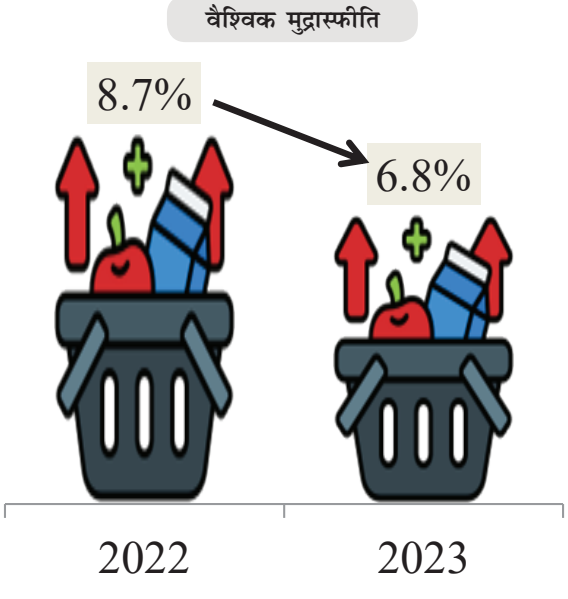

बार-बार आने वाले व्यवधानों से वैश्विक व्यापारिक व्यापार की मात्रा में वृद्धि धीमी हो जाती है

सेवा व्यापार में वृद्धि से वस्तु व्यापार में संकुचन की आंशिक भरपाई हुई

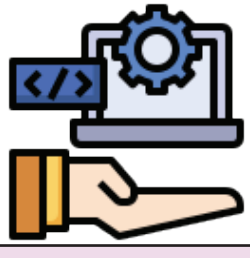

2023 में माल के वैश्विक निर्यात की मात्रा में वृद्धि= (–) 0.4%

2023 में वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक निर्यात की मात्रा में वृद्धि=0.5%

स्थिर निजी खपत और विकास के चालक के रूप में उभरते निवेश के साथ भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद है

जीडीपी वृद्धि में निरंतर गति

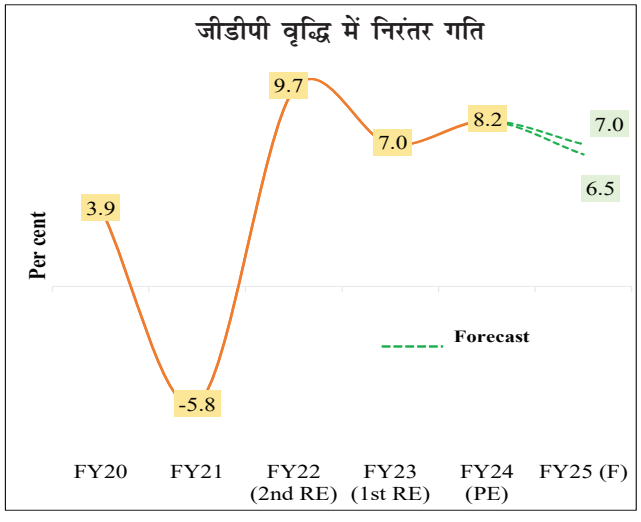

मौजूदा कीमतों पर जीडीपी में हिस्सेदारी

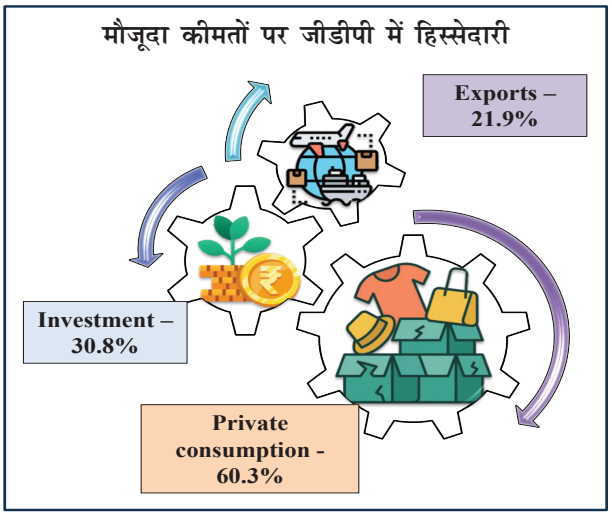

निवेश निजी और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय द्वारा संचालित हो रहा है, जिसमें घरेलू निवेशक भी योगदान दे रहे हैं

निजी निवेश में सरकारी पूंजीगत व्यय की भीड़

*Axis bank research

आवास में निवेश की बढ़ती भूख

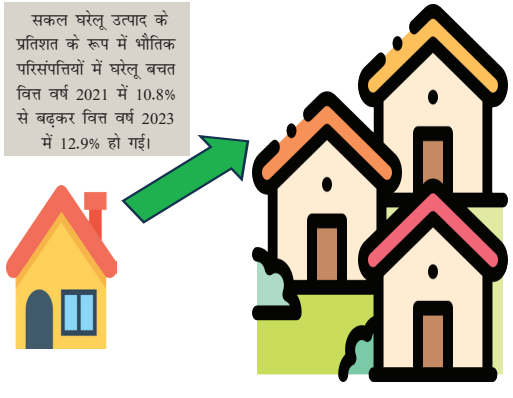

केंद्र सरकार के व्यय की गुणवत्ता बेहतर हो रही है

कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अधिक हिस्सा

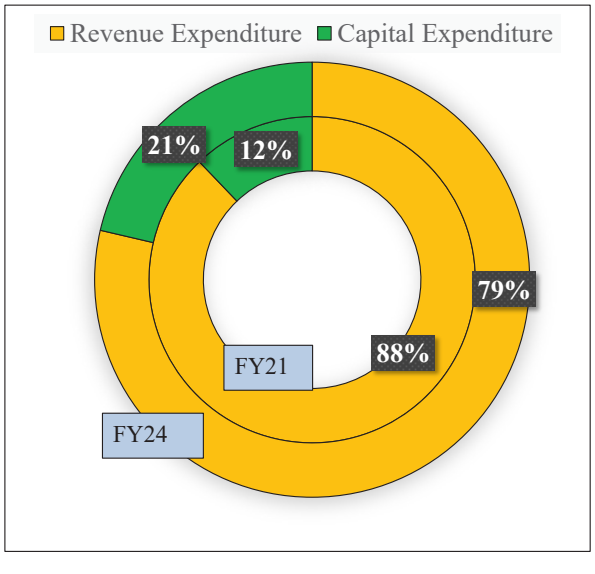

राजकोषीय घाटे में कमी से निवेश में वृद्धि का संकेत मिलता है

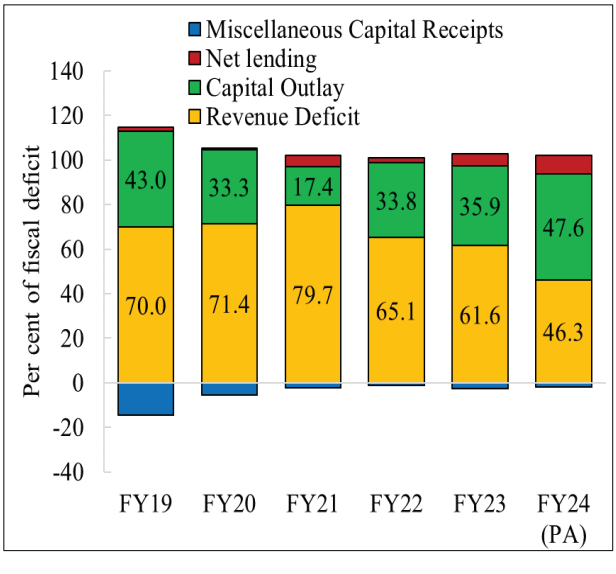

अपेक्षाकृत कम घरेलू मुद्रास्फीति, उच्च विकास और स्थिर बाह्य क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था को लचीलापन प्रदान कर रहे हैं

भारत एक उच्च-विकास और निम्न-मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था है

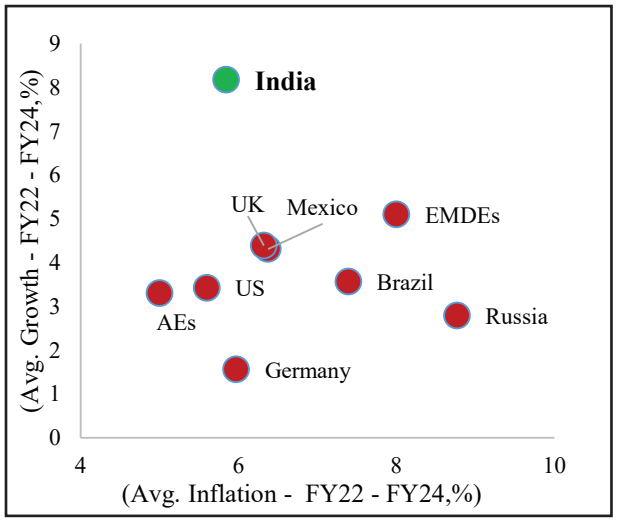

अप्रैल 2023 से जून 2024 के दौरान रुपया सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक था

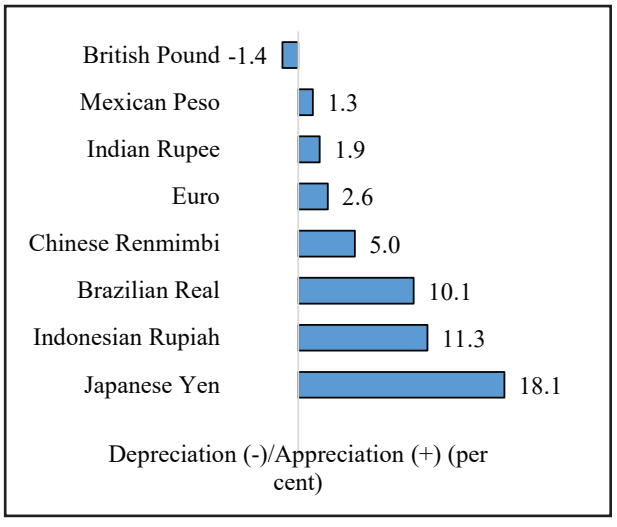

परिणामस्वरूप, व्यापक आर्थिक स्थिरता विकास को सुरक्षित रख रही है

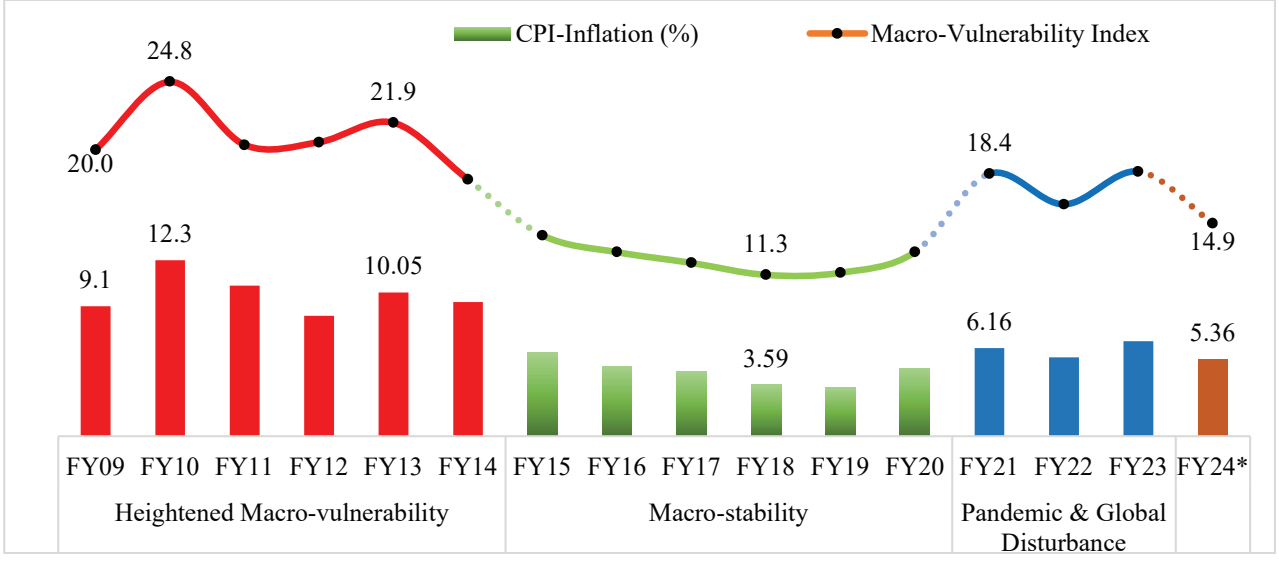

सरकार विकास की समावेशिता सुनिश्चित कर रही है

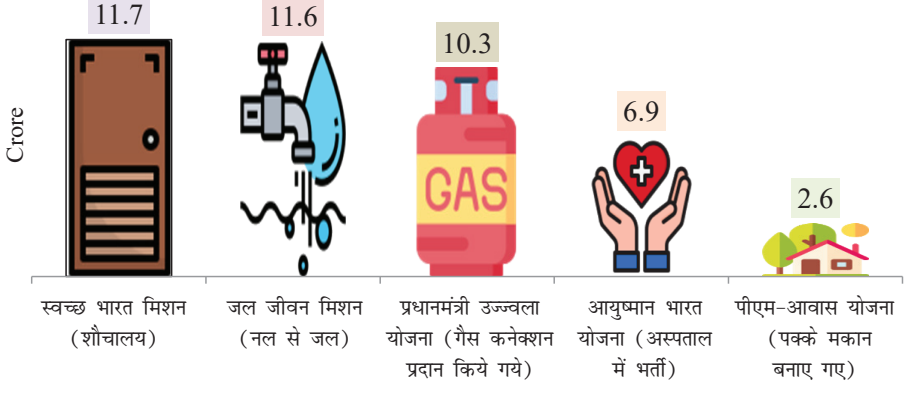

प्रारंभ से ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

बैंक ऋण में दोहरे अंक की वृद्धि

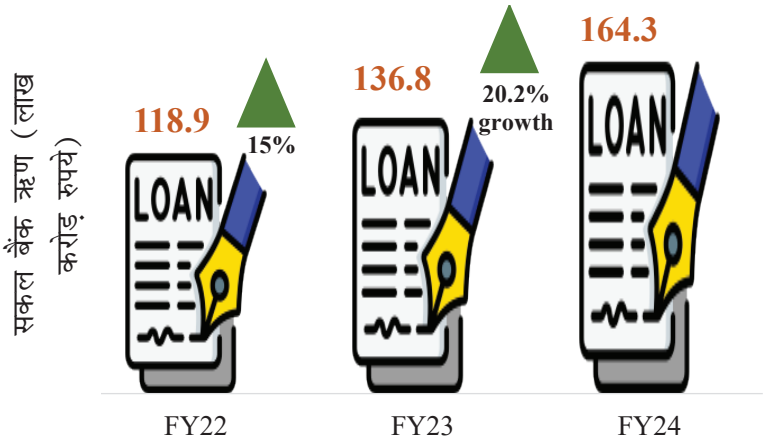

भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: अर्थव्यवस्था के पहिये को गति देना

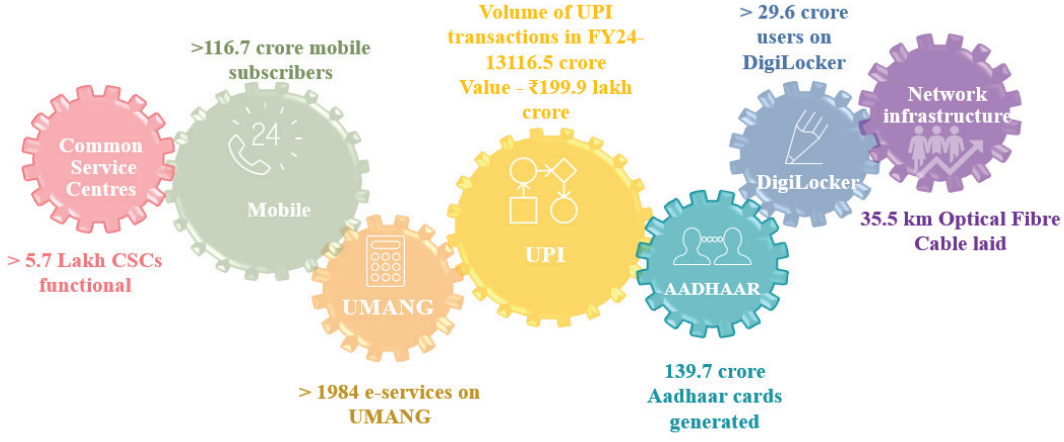

माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई): वित्तीय समावेशन की सुविधा

एमएफआई द्वारा वितरित ऋणों में वृद्धि

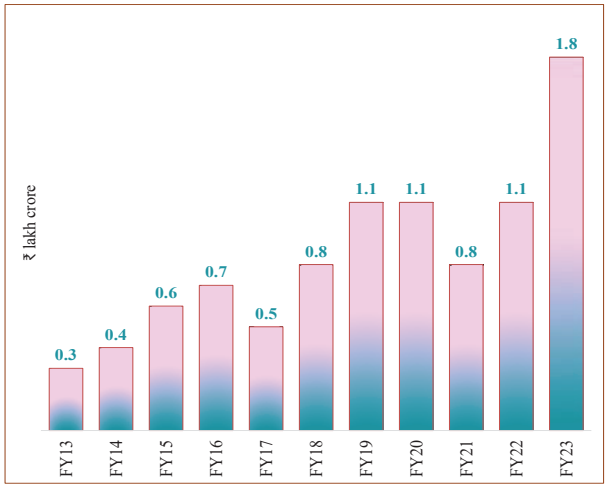

भारत में दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोफा. इनेंस क्षेत्र है

एमएफआई के कुल ग्राहकों में 98 प्रतिशत महिलाएं हैं

सूक्ष्म-ऋण के तहत एमएफआई ने 532 लाख से अधिक ग्राहकों तक पहुंच बनाई है, जिन पर कुल 1.8 लाख करोड़ रुपये का ऋण बकाया है

आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक में मार्च 2023 में 60.1 से मार्च 2024 में 64.2 तक की वृद्धि भारत में वित्तीय क्षेत्र की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में सुधार का संकेत देती है

गिफ्ट सिटी: भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है

वित्त वर्ष 24 में भारतीय पूंजी बाजार उभरते बाजारों में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले बाजारों में से एक बनकर उभरा।

प्राथमिक बाजार

प्राथमिक बाजारों ने वित्त वर्ष 2024 में 10.9 लाख करोड़ का पूंजी निर्माण किया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 9.3 लाख करोड़ था

द्वितीयक बाजार

भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स वित्त वर्ष 24 के दौरान 26.8 प्रतिशत चढ़ा, जबकि वित्त वर्ष 23 के दौरान यह (–)8.2 प्रतिशत था

बाजार पूंजीकरण

भारत का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2019 में 77% से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 124% हो गया।

म्यूचुअल फंड्स

वित्त वर्ष 24 के अंत में म्यूचुअल फंड की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां 14 लाख करोड़ बढ़कर 53.4 लाख करोड़ हो गईं।

व्यवस्थित निवेश योजना

वार्षिक निवल एसआईपी प्रवाह वित्त वर्ष 2021 में 0.96 लाख करोड़ से दोगुना होकर वित्त वर्ष 2024 में 2 लाख करोड़ हो गया

कीमतें और मुद्रास्फीतिः नियंत्रण में

2023 में भारत की मुद्रास्फीति ईएमडीई से कम होगी

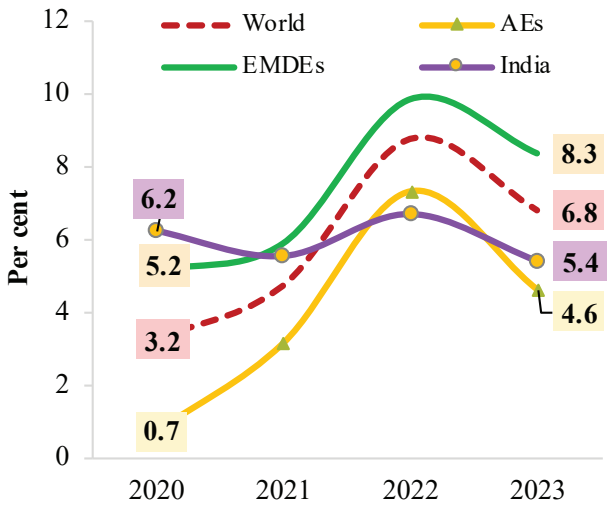

भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य से सबसे कम औसत विचलन (2021-2023) है

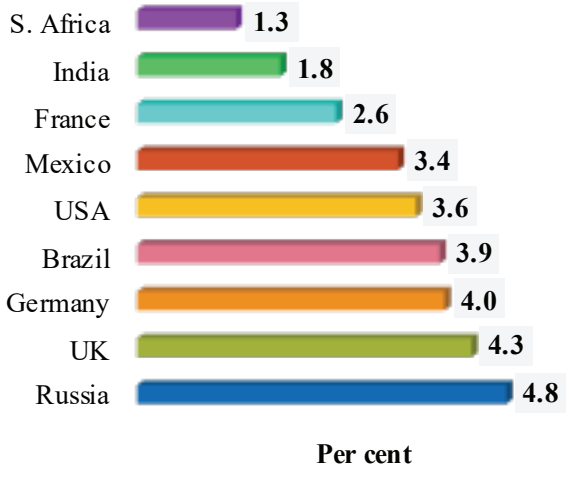

वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति सबसे कम रही

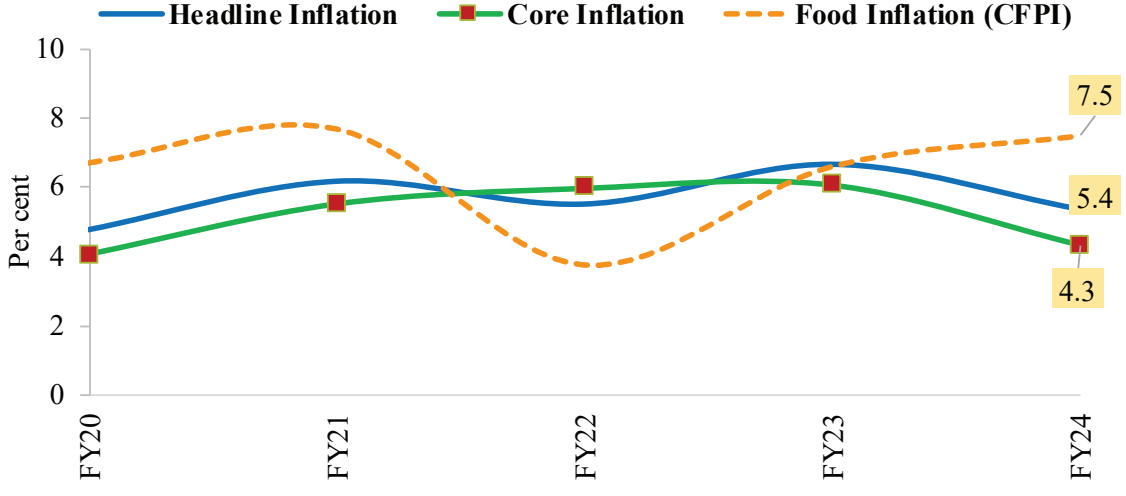

मौद्रिक नीति का प्रभाव मुख्य मुद्रास्फीति के 4 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने से स्पष्ट है

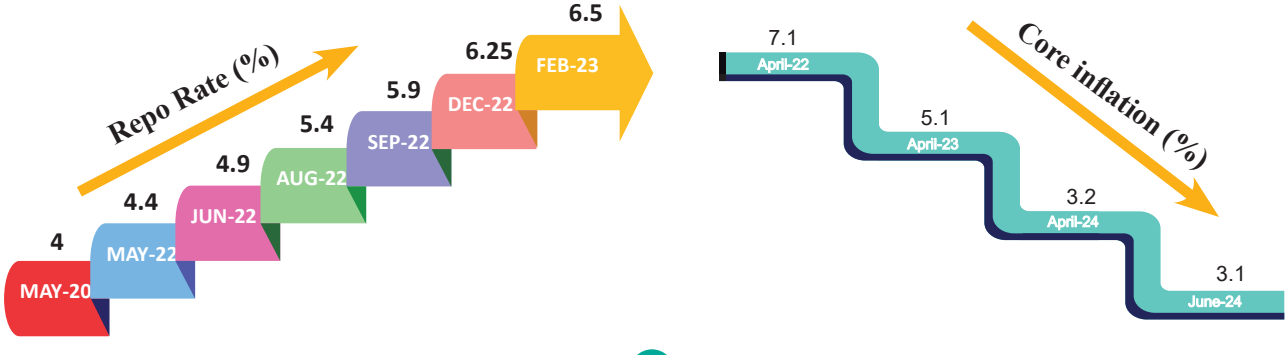

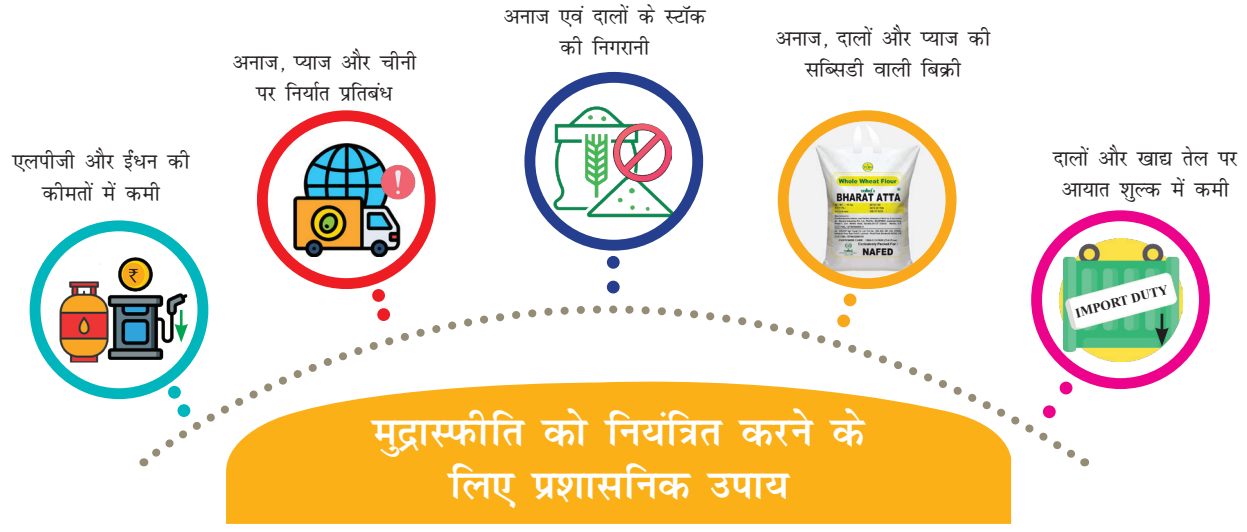

एलपीजी और ईंधन मुद्रास्फीति पर सरकारी मध्यक्षेप का प्रभाव

मूल्य कटौती/सब्सिडी के कारण एलपीजी मुद्रास्फीति में कमी

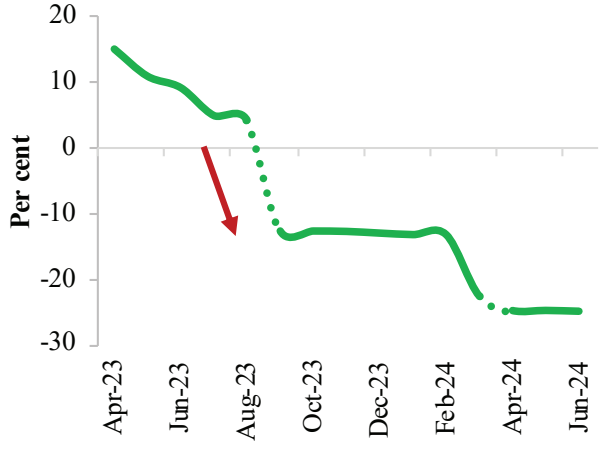

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के कारण महंगाई में कमी

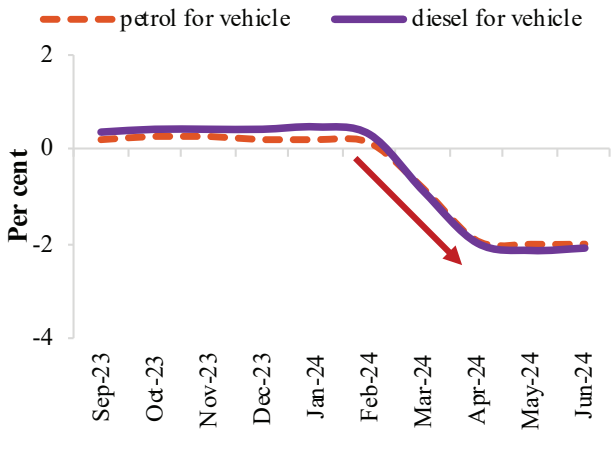

वित्त वर्ष 2024 में चयनित राज्यों में ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति का अंतर

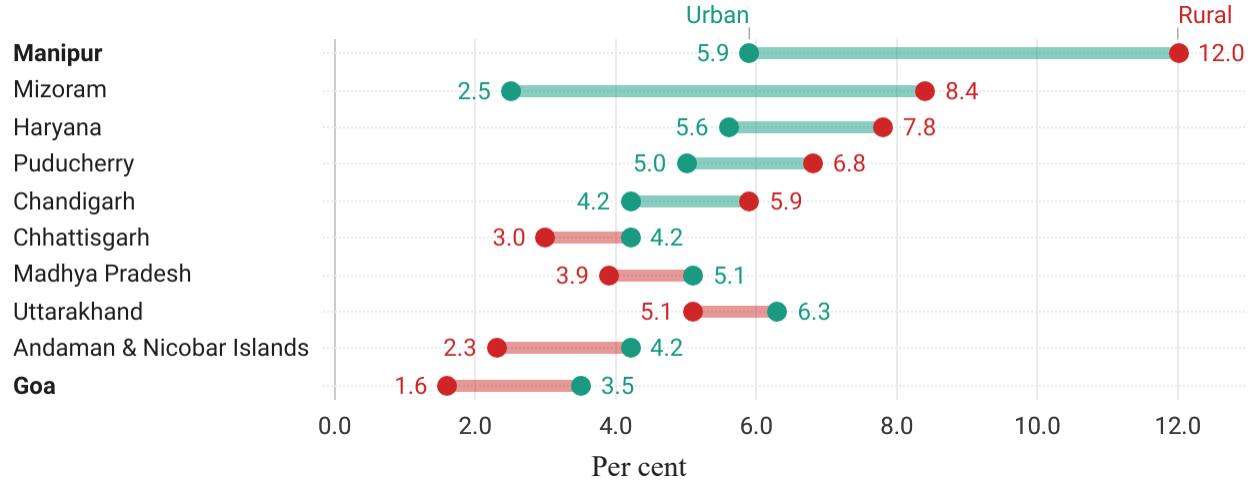

उच्च मुद्रास्फीति वाले राज्यों' में ग्रामीण-शहरी अंतर अधिक है (वित्त वर्ष 24)

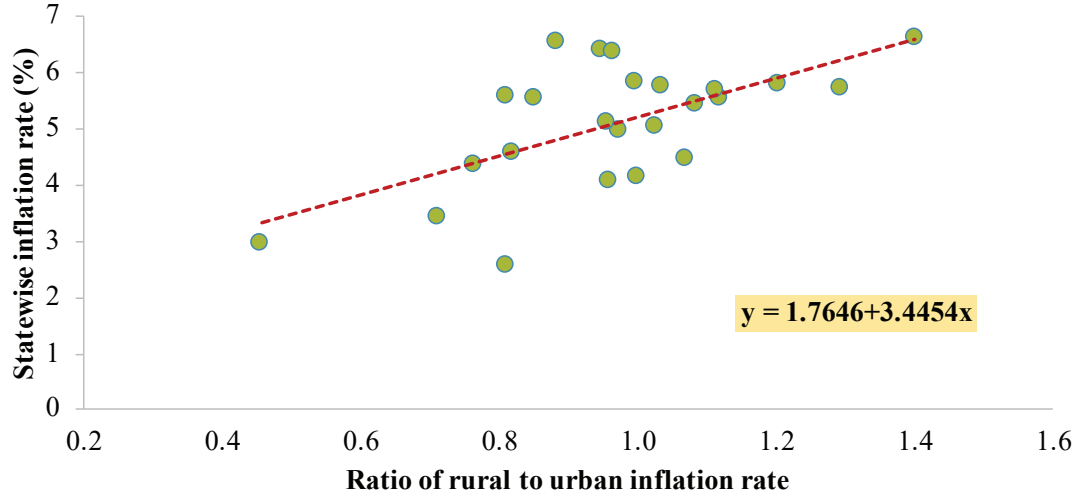

* यह स्कैटर प्लॉट 23 प्रमुख राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-नमूने पर आधारित है

वैश्विक कमोडिटी कीमतों में गिरावट भारत के मुद्रास्फीति परिदृश्य के लिए अच्छा संकेत है

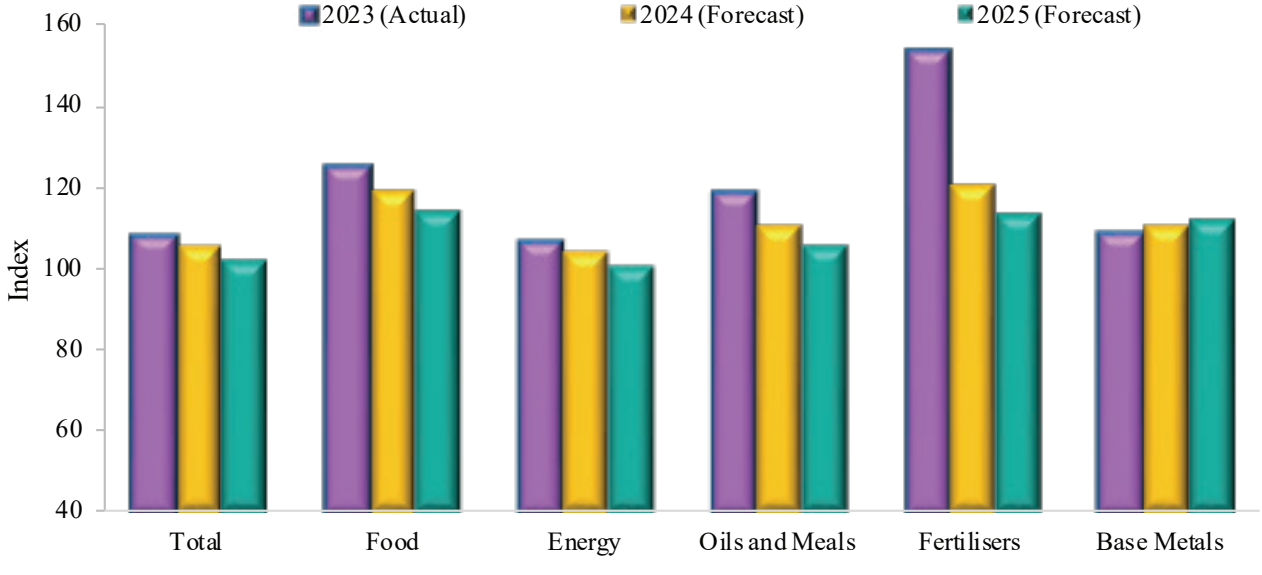

बाह्य क्षेत्र: समृद्धि के बीच स्थिरता

भारत का सेवा निर्यात नौ वर्षों में दोगुना से अधिक

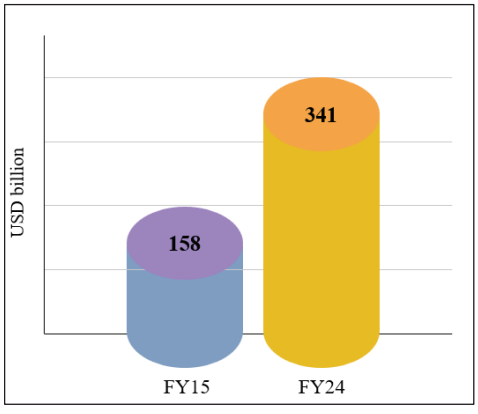

- **4.3%** ◆ विश्व सेवाा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात हिस्सा
- **2nd** ◆ विश्व के दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में स्थान
- **6th** ◆ विश्व के व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं के निर्यात में स्थान
- **8th** ◆ विश्व के अन्य व्यावसायिक सेवा निर्यातों में स्थान

भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों की उल्लेखनीय वृद्धि

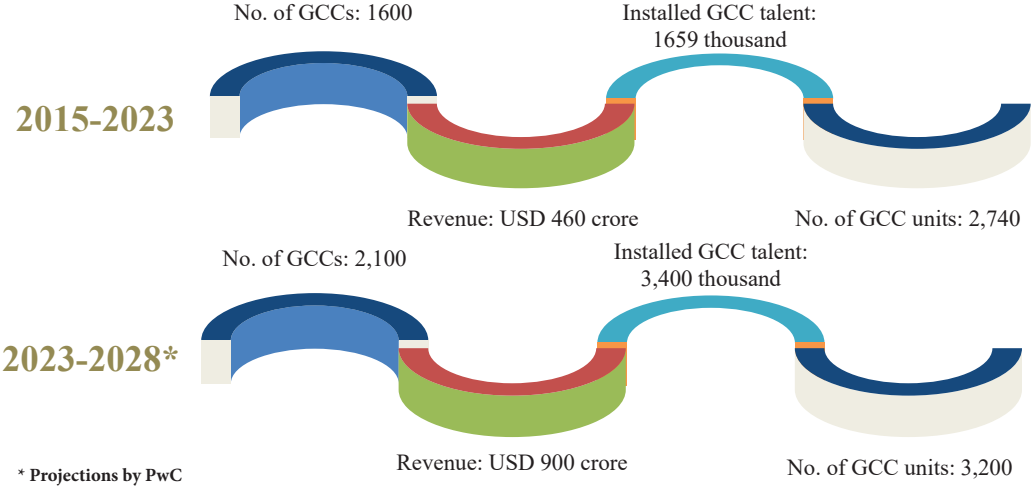

* Projections by PwC

लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार

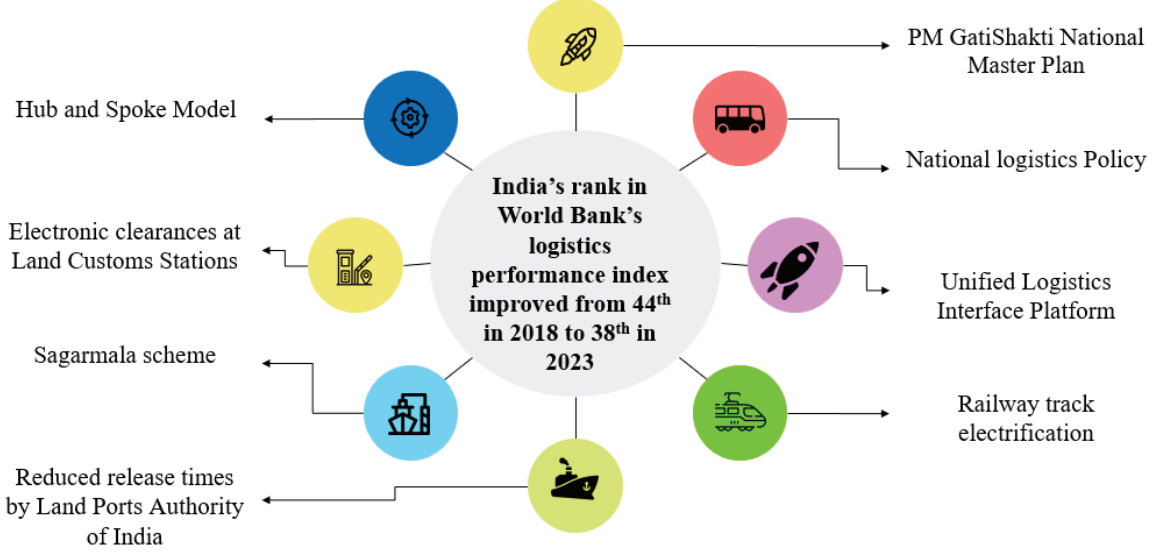

चाईना प्लस वन स्ट्रेटजी से भारत को कैसे लाभ हो सकता है?

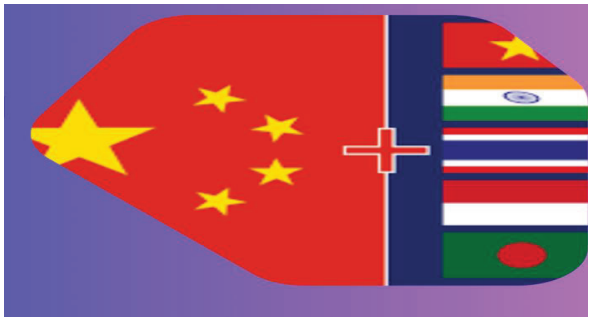

चाइना प्लस वन से भारत को कैसे लाभ हो सकता है?

- चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ✓
- चीन से आयात बढ़ाएँ ✗

चीन से व्यापार में बदलाव का प्रमाण भारत द्वारा अमेरिका को किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में वृद्धि से परिलक्षित होता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार अधिशेष में वृद्धि हुई है।

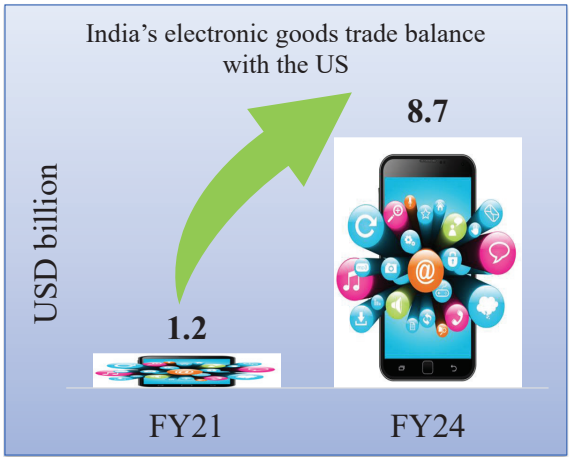

भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी में वृद्धि

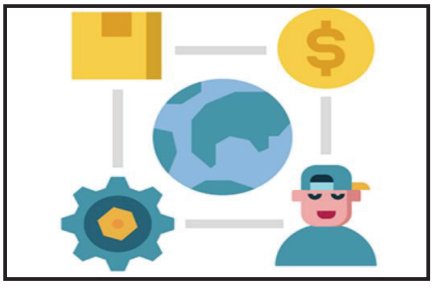

सकल व्यापार में जी.वी.सी. से संबंधित व्यापार की हिस्सेदारी में वृद्धि

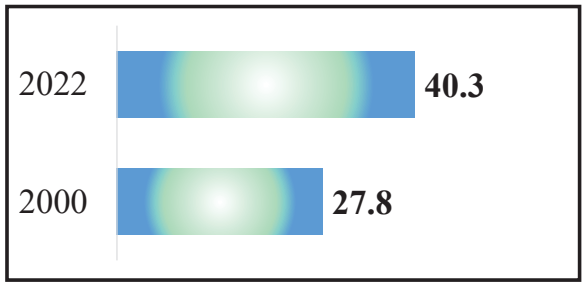

- मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण की हिस्सेदारी में वृद्धि
- सेवा क्षेत्र में उच्च मूल्य वर्धित सेवाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि
- भारत ने तैयार माल के निर्यात में वृद्धि के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है

नीति प्राथमिकताएँ

- गुणवत्तापूर्ण व्यापार अवसंरचना का विकास करना
- जी.वी.सी. नेटवर्क में एम.एस.एस.इ. को एकीकृत करना
- छोटे व्यवसायों के प्रवेश और निकास की प्रक्रियाओं को सरल बनाना
- व्यापार सुविधा उपायों की दिशा में कार्य करना

सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में बाह्य ऋण में गिरावट

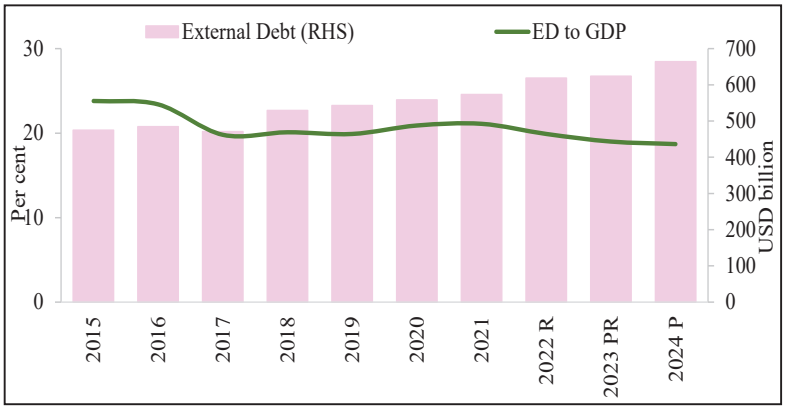

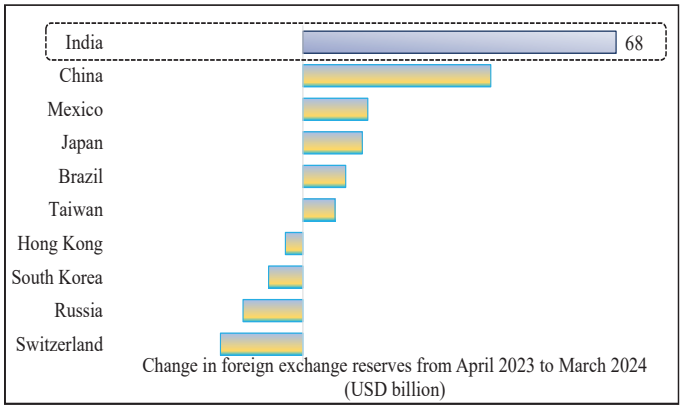

वित्त वर्ष 2024 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई

वित्त वर्ष 2015 के बाद वित्त वर्ष 2024 में एफपीआई प्रवाह का उच्चतम स्तर

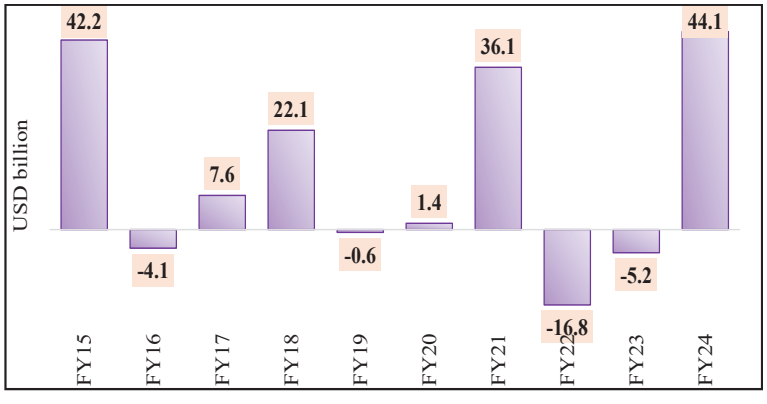

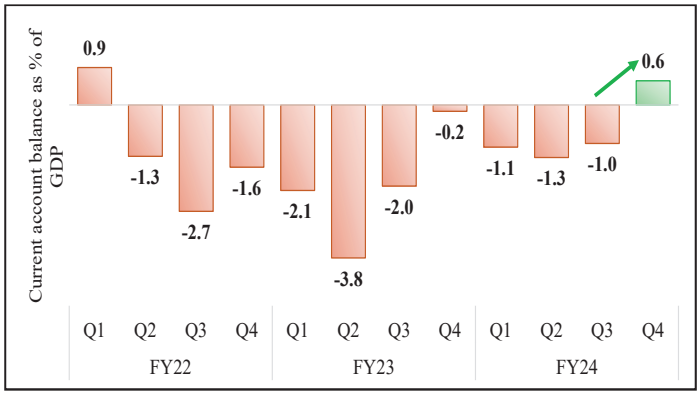

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में चालू खाता अधिशेष के कारण वित्त वर्ष 2024 में चालू खाता घाटे में कमी

अमृत काल के लिए विकास रणनीतिः मजबूत, टिकाऊ और समावेशी

अमृत काल के लिए विकास रणनीतिः मजबूत, टिकाऊ और समावेशी

1. अनुकूल नीति और विनियामक वातावरण के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 35 प्रतिशत तक बढ़ाना

2. राज्य और स्थानीय सरकार के स्तर पर विनियमन को समाप्त करके भारत के एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाना। **एमएसएमई** उद्यमियों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट, अनुरूप कौशल विकास पर जोर देना और एक स्पष्ट निर्यात रणनीति विकसित करना।

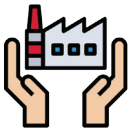

3. कृषि क्षेत्र में विकास की बाधाओं को दूर करें और बाजारों को किसान के हित में काम करने दें।

4. भारत में हरित परिवर्तन के लिए सुरक्षित वित्तपोषण।

5. **शिक्षा-रोजगार के बीच** की खाई को पाटना

6. राज्य की क्षमता और सक्षमता का निर्माण

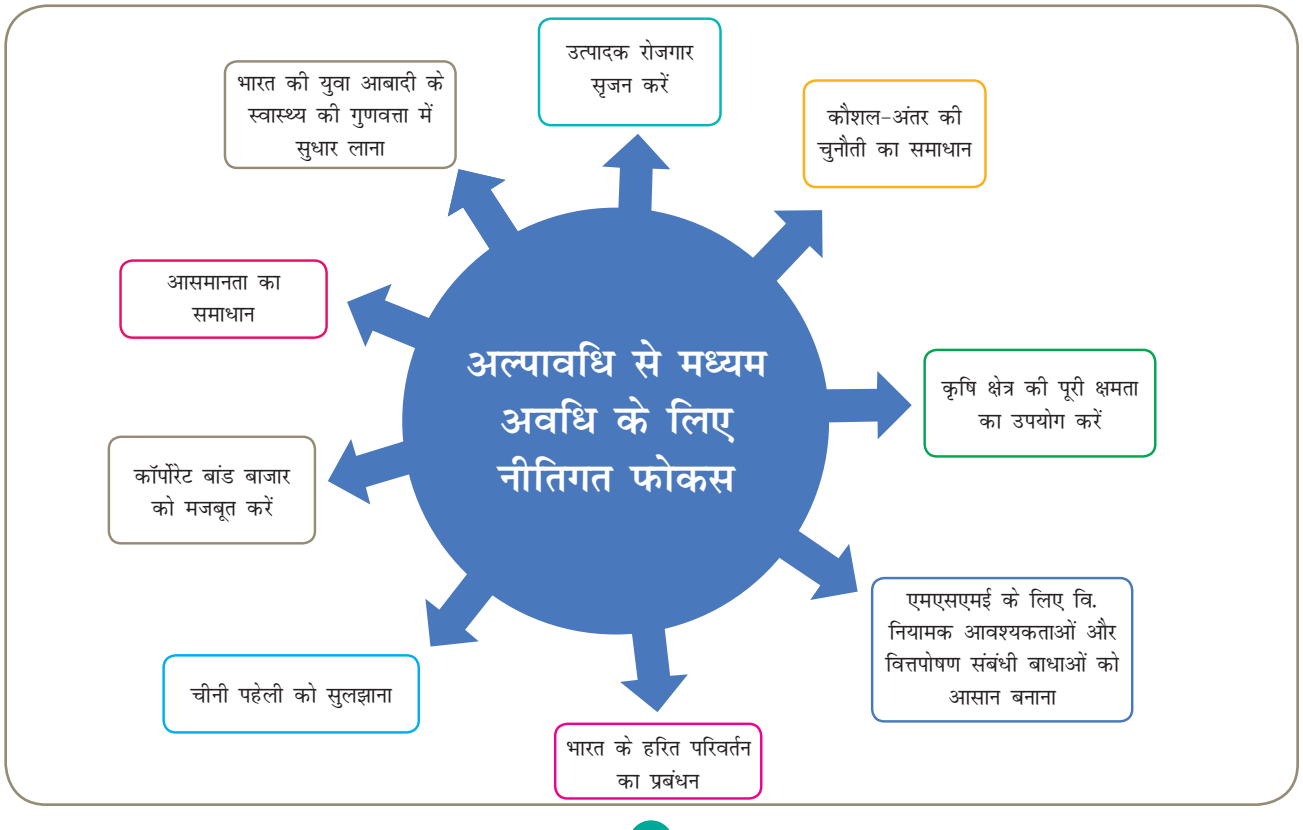

जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण: समझौताकारी सामंजस्य

भारत की जलवायु कार्रवाई की वर्तमान स्थिति

सौर ऊर्जा

- 2023-24 में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 15.03 गीगावाट की वृद्धि।
- 30 अप्रैल 2024 तक संचयी 82.64 गीगावाट स्थापित और क्षमता।

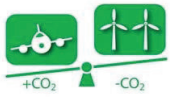

उत्सर्जन तीव्रता

- भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 2019 में 33प्रतिश कम हुई (2005 के स्तर से)

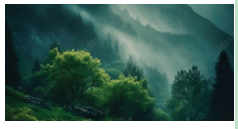

कार्बन सिंक के रूप में वृक्ष और वन क्षेत्र

- 2005 से 2019 तक 1.97 बिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन लिंक पहले ही बनाया जा चुका है।

स्थापित विद्युत क्षमता 30 अप्रैल 2024: 442.8 गीगावाट

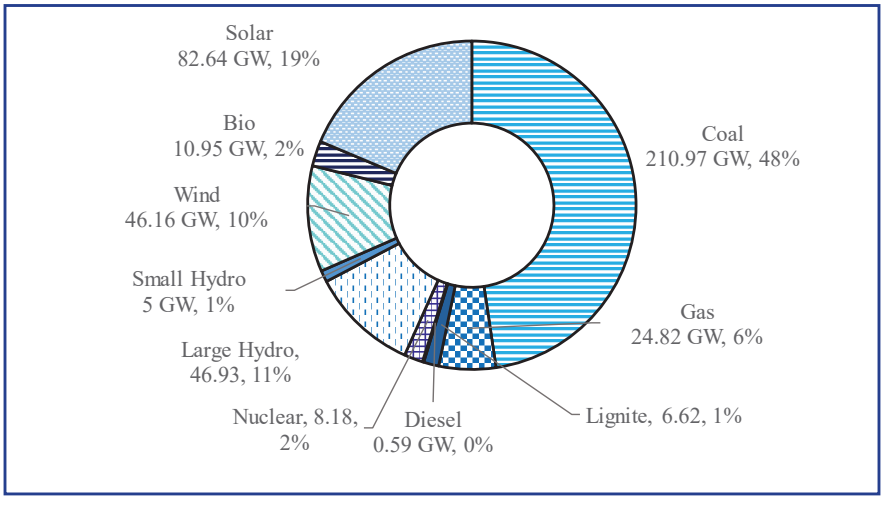

महत्वपूर्ण और दुर्लभ भू-खनिज सांद्रता

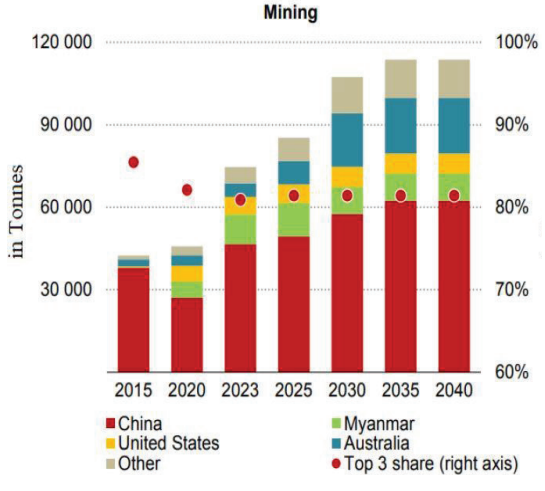

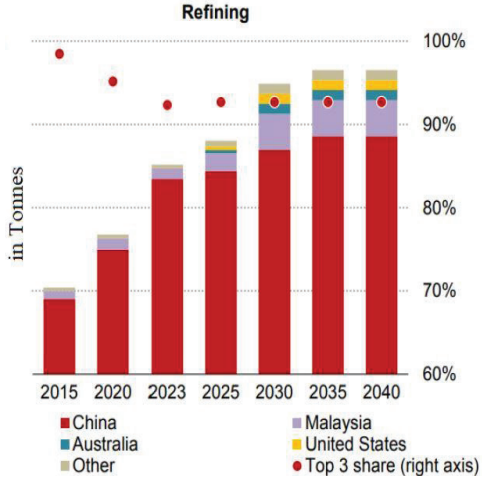

पीएम-सूर्य घर योजना

- कुल परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये
  - छत पर सोलर लगाना
    - 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
    - लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना
  - छत पर सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावाट और सौर क्षमता का संवर्धन
- 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी

ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- पर्यावरण के लिए जीवनशैली (एलआईएफ़ई) मिशन
  - प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी)
    - ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)
    - शून्य लेबलिंग कार्यक्रम
  - मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम
- सभी @ 24 अभियान

सामाजिक क्षेत्र: कल्याण जो सशक्त करे

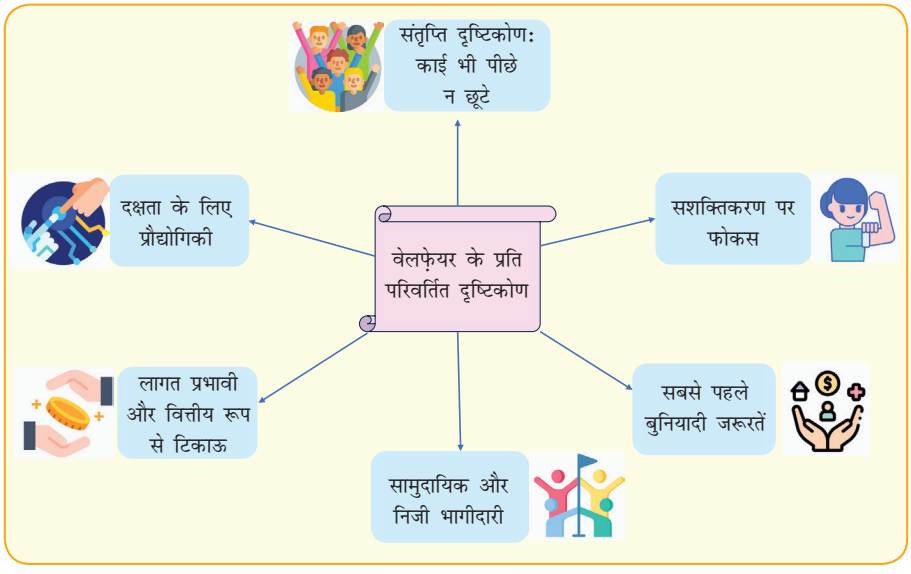

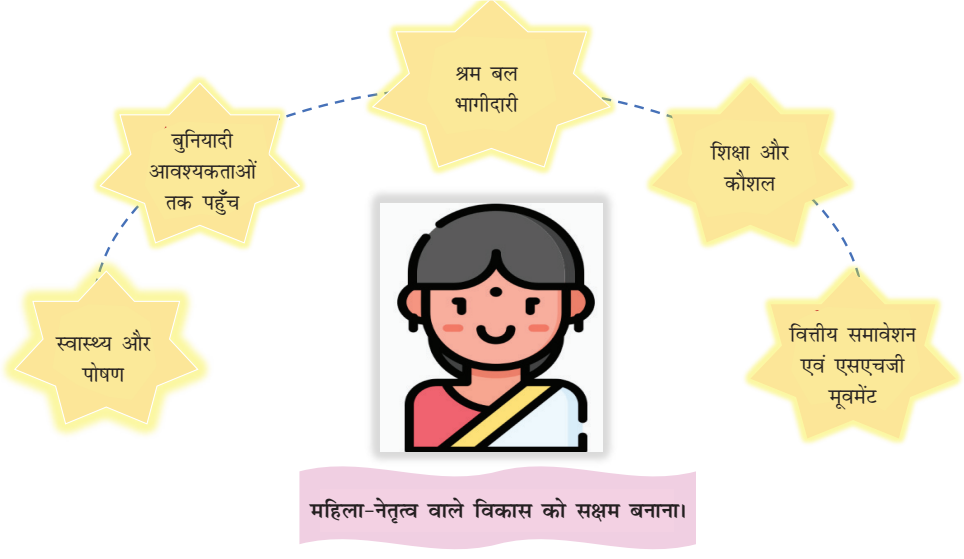

* राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16
* मैकग्राथ एवं अन्या.. 2023

रोजगार और कौशल विकास: गुणवत्ता की ओर

नौकरियों का उभरता परिदृश्य

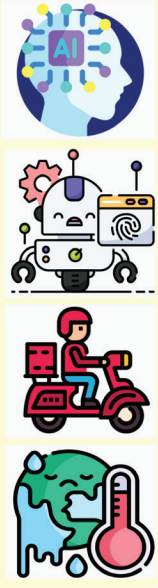

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: एआई का अल्पावधि दीर्घावधि प्रभाव
- कुछ नौकरियों को प्रतिस्थापित करना और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ावा देना।
- तकनीकी विकल्प राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है-ऐसमोग्लू एवं जॉनसन 2024
- एआई में आर खंड डी की आवश्यकता और नौकरियों पर एआई के प्रभाव की योजना
- गिग कार्य का उदय- सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता
- जलवायु परिवर्तन और उर्जा संक्रमण: उत्पादकता में की के साथ-साथ नए क्षेत्रों में रोजगार सृजन

पीएलएफएस के अनुसार श्रम बाजार संकेतकों में सुधार

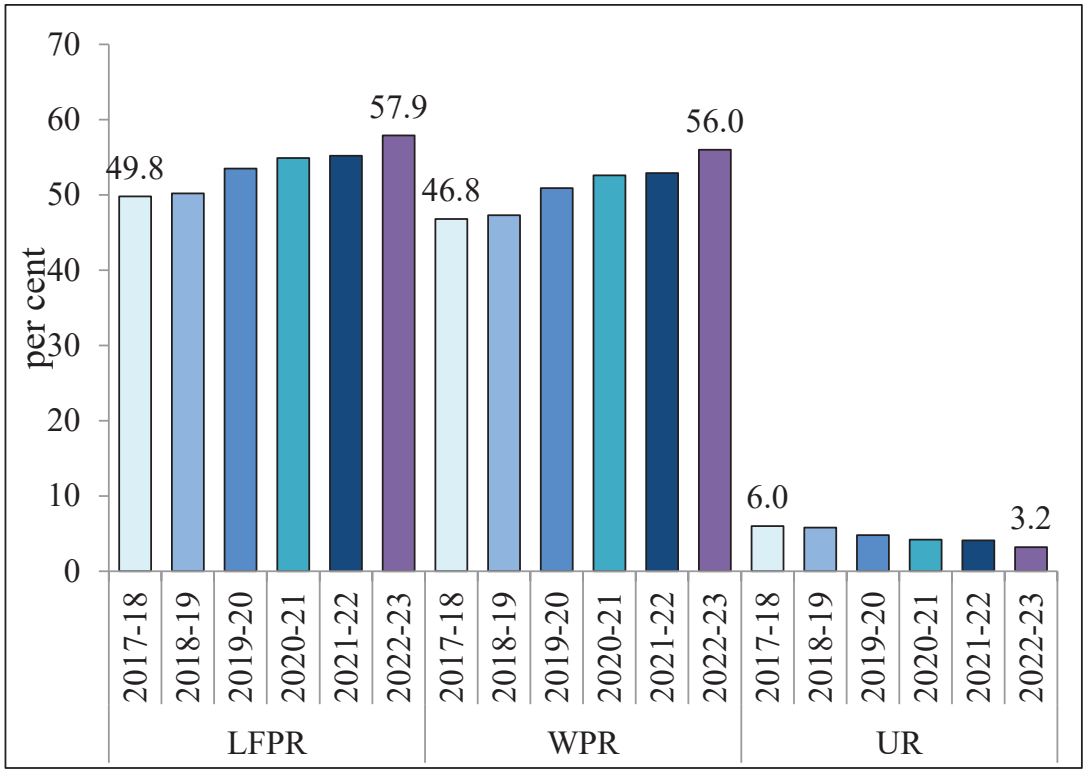

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वार्षिक रिपोर्ट। एमओएसपीआई

नोट: एलएफपीआर श्रम बल भागीदारी दर डबल्यूपीआर श्रमिक जनसंया अनुपात यूआर बेरोजगारी दर

कारखानों का उन्नयन और संगठित विनिर्माण रोजगार वृद्धि

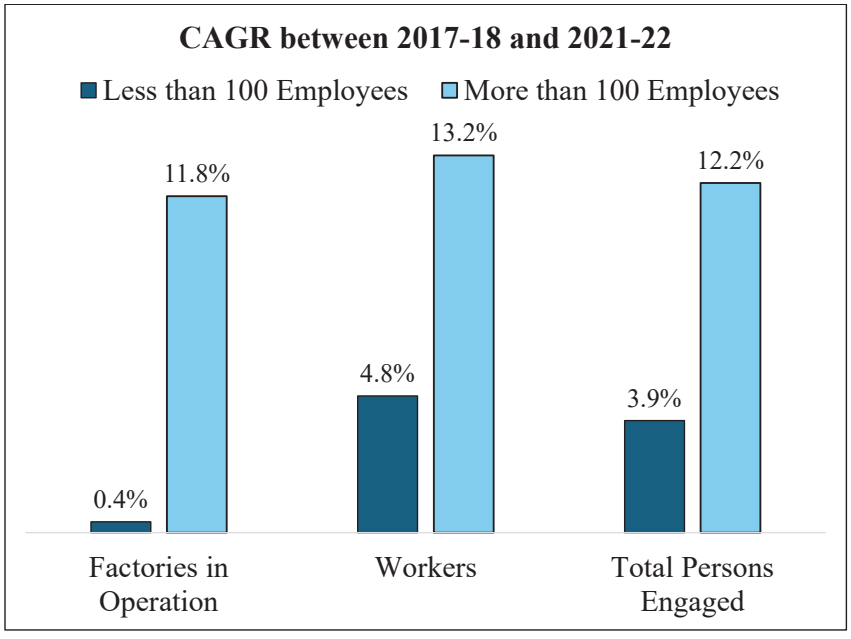

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

गैर-कृषि रोजगार सृजन के लिए वार्षिक आवश्यकता 2024-2036

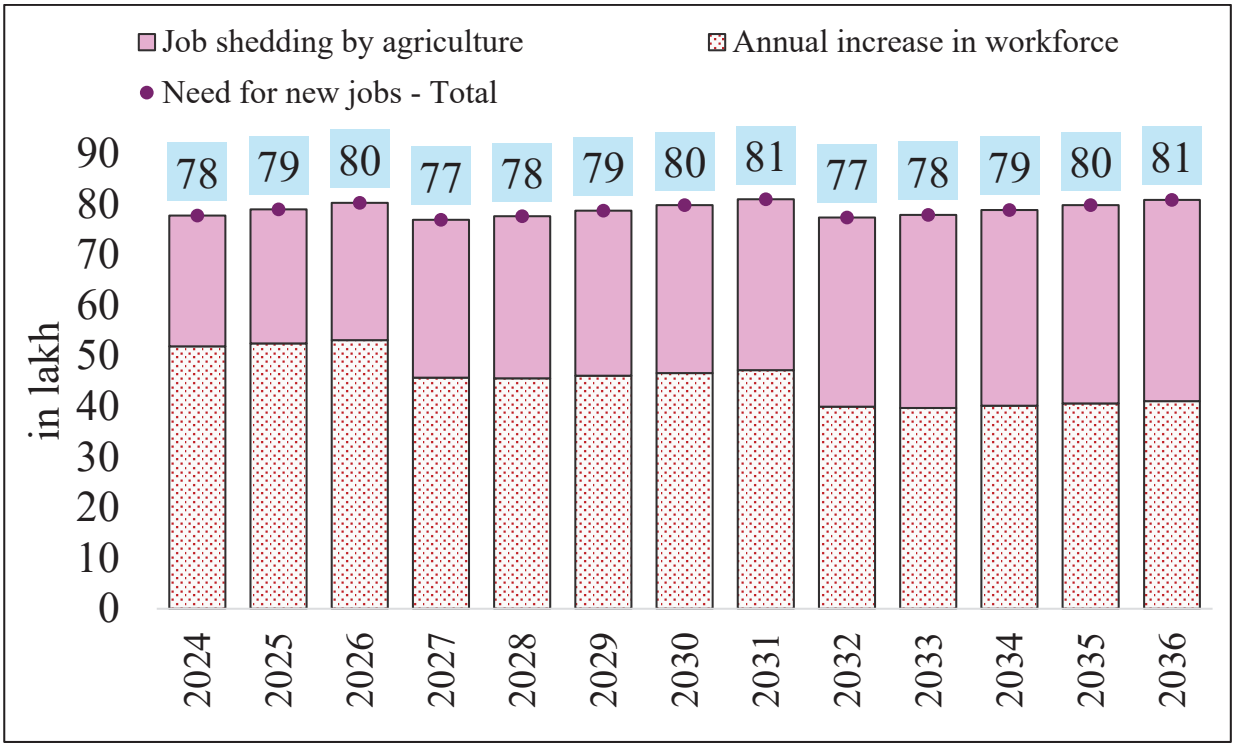

- कार्यबल भागीदारी दरों और कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी के बारे में मान्यताओं पर आधारित गणना
- भारतीय अर्थव्यवस्था को गैर-कृषि में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियाँ सृजित करने की जरूरत है
- मात्रा और गुणवत्ता-दोनों मायने रखते हैं

कृषि और खाद्य प्रबंधनः यदि हम सही से कर लें तो कृषि में बढ़ोतरी

भारत का कृषि क्षेत्र लचीलापन और विविधतापूर्ण विकास दर्शाता है, तथा हाल के वर्षों में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी तय करना-किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना

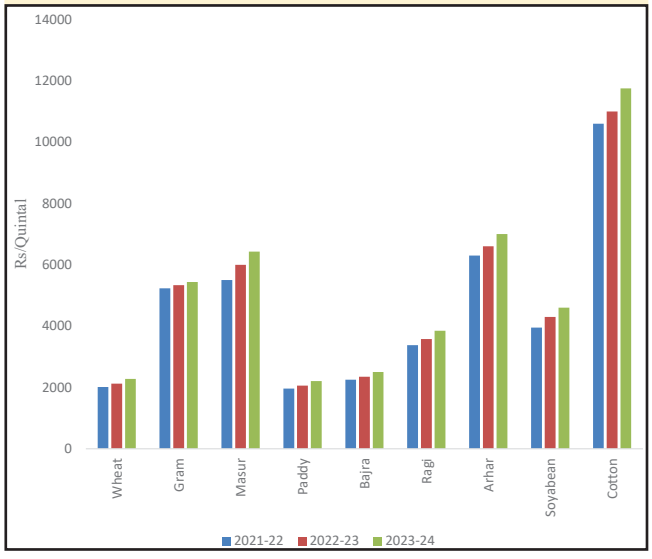

भारतीय कृषि के संबद्ध क्षेत्र लगातार मजबूत विकास केन्द्रों और कृषि आय में सुधार के आशाजनक स्रोतों के रूप में उभर रहे हैं।

पशुधन क्षेत्र में वृद्धि से दूध, अंडे और मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

मत्स्य पालन क्षेत्र 2014-15 और 2022-23 के बीच (स्थिर मूल्यों पर) 8.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है।

कुल जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा

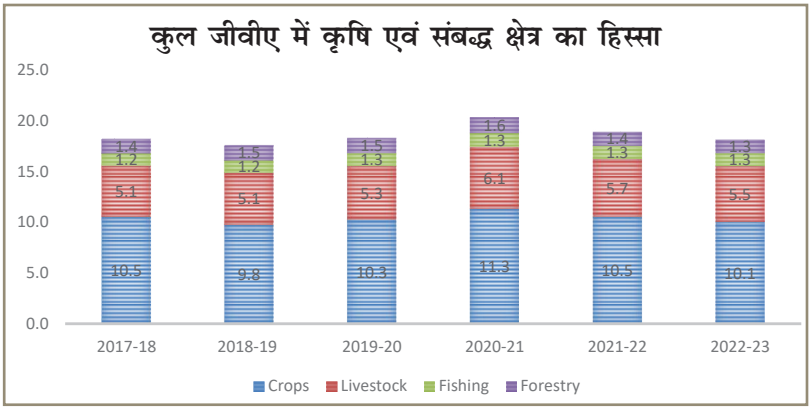

चयनित उत्पादों में वृद्धि

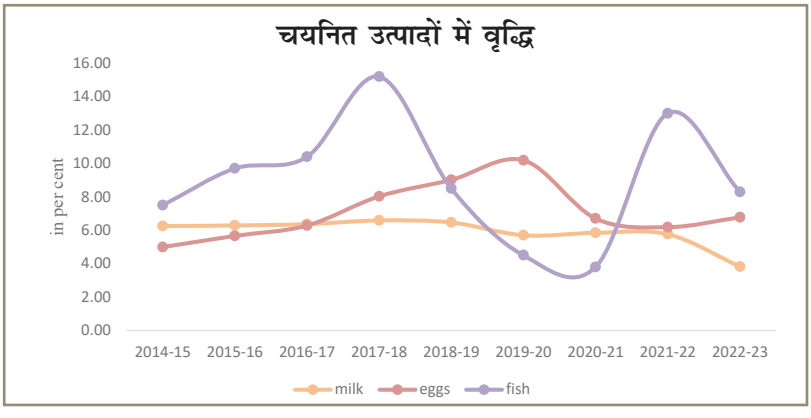

उद्योग: लघु एवं मध्यम दोनों अपरिहार्य

वित्त वर्ष 24 में औद्योगिक विकास से आर्थिक विकास को बल मिलेगा

उद्योग और उसके घटकों की वार्षिक वृद्धि

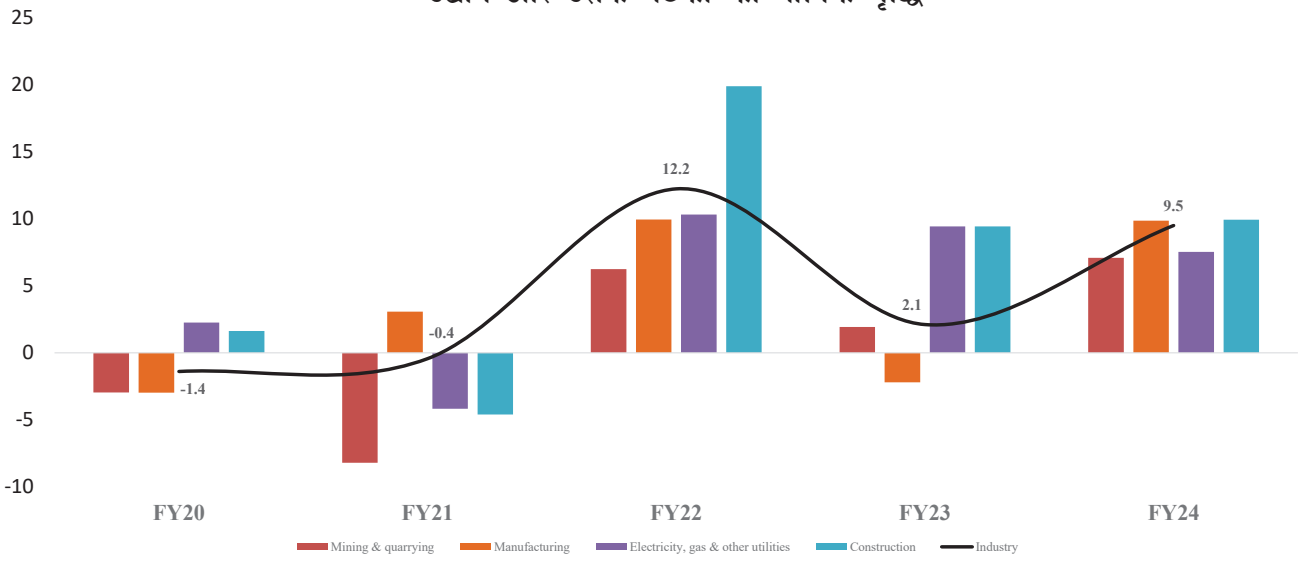

प्रमुख औद्योगिक मध्यस्थ

- कोयला: उत्पादन में तेजी, आयात पर निर्भरता में कमी
- इस्पात: वर्ष 2024 में उच्चतम उत्पादन खपत

घरेलू खपत के % के रूप में कोयला उत्पादन में सुधार

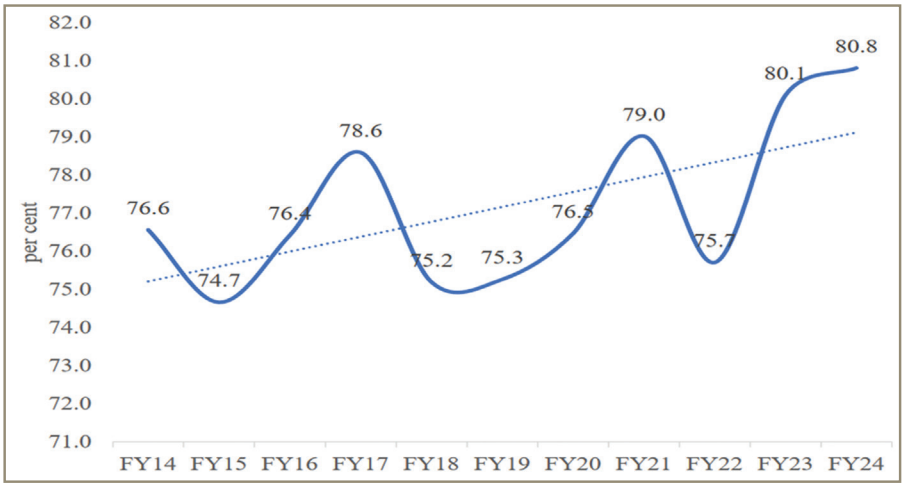

भारत पिछले 5 वर्षों में से 4 वर्षों में परिष्कृत इस्पात का शुद्ध निर्यातक रहा

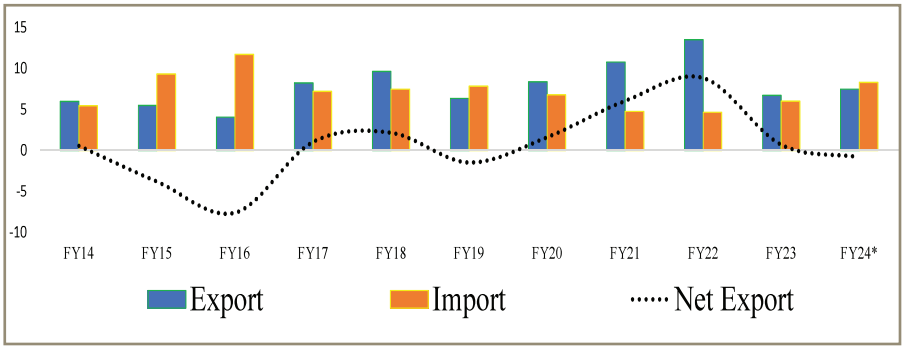

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और निर्यात में वृद्धि

(% में वद्धि)

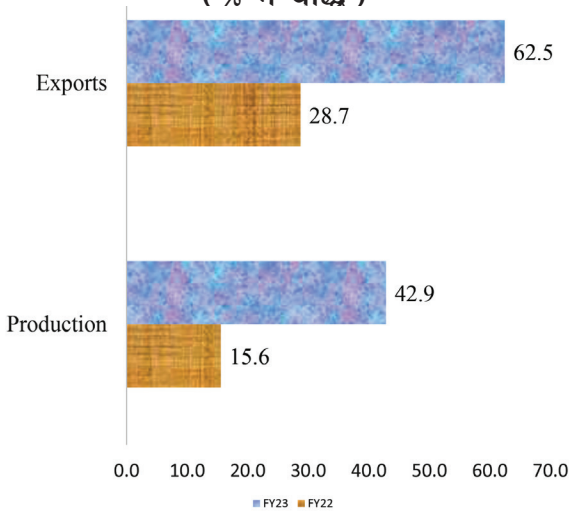

ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में जोरदार ग्रोथ

वित्त वर्ष 24 में

7.1%

16.0%

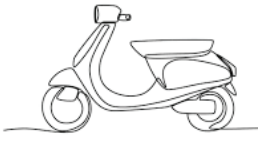

10.3%

विश्व की फार्मेसी

- वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 21 में दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं विकास व्यय बिक्री कारोबार का 5% था
- भारत का दवा बाजार, मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है
- शीर्ष 20 वैश्विक जेनरिक कंपनियों में से 8 भारत में स्थित हैं
- सभी जिलों में 12500 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए
- नवाचार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है
- अनुसंधान एवं विकास, उद्यम पूंजी और एंजेल निवेशकों से वित्त पोषण के चौनल बढ़ाने की आवश्यकता है

मई 24 तक पीएलआई के अंतर्गत प्रगति

- ₹1.28 लाख करोड़ से अधिक निवेश
- 8.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
- निर्यात में 4 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि
- 10.8 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन/ बिक्री

एमएसएमई: सीजीटीएमएसई के तहत स्वीकृत गारंटी में काफी वृद्धि हुई

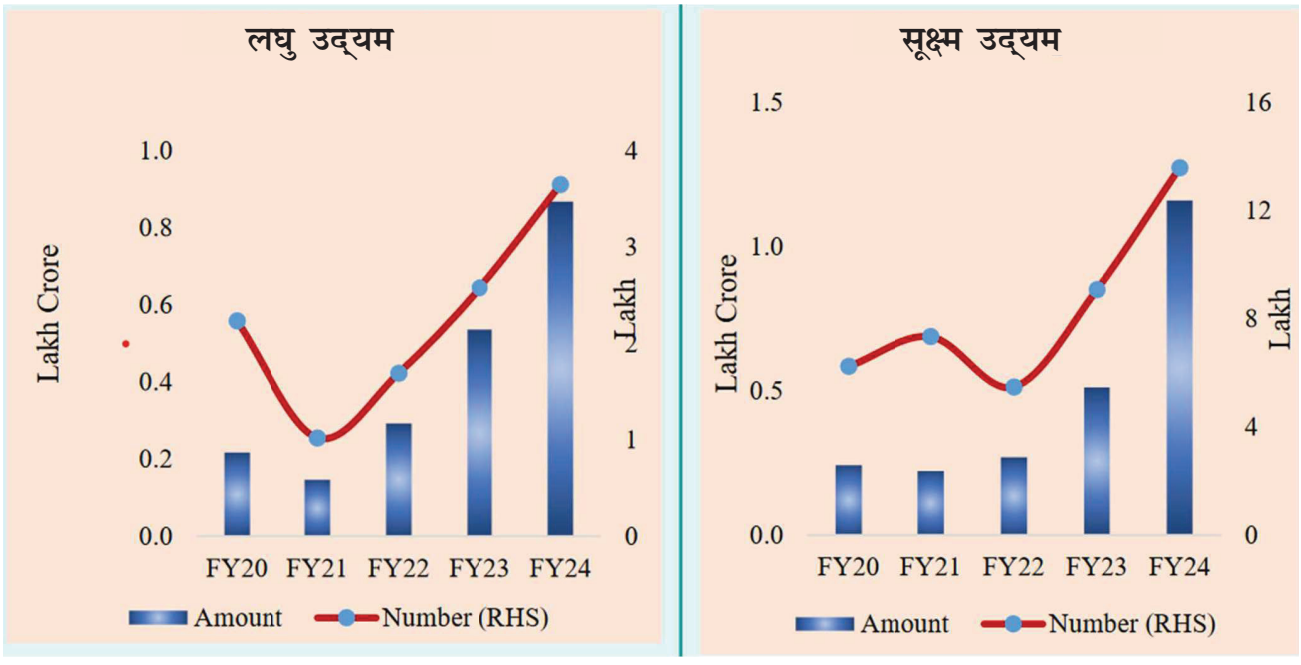

फलते-फूलते स्टार्ट-अप और नवोन्मेषी इको सिस्टम

वित्त वर्ष 24 के अंत तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में 13,000 से अधिक डीपीआईआई. टी-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप होंगे।

स्वीकृत पेटेंटों की संख्या वित्त वर्ष 15 में 5978 में 17 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 103057 हो गई।

सेवाएँ: विकास के अवसरों को बढ़ावा देना

सेवा क्षेत्र में जीवीए की बढ़ती प्रवृत्ति

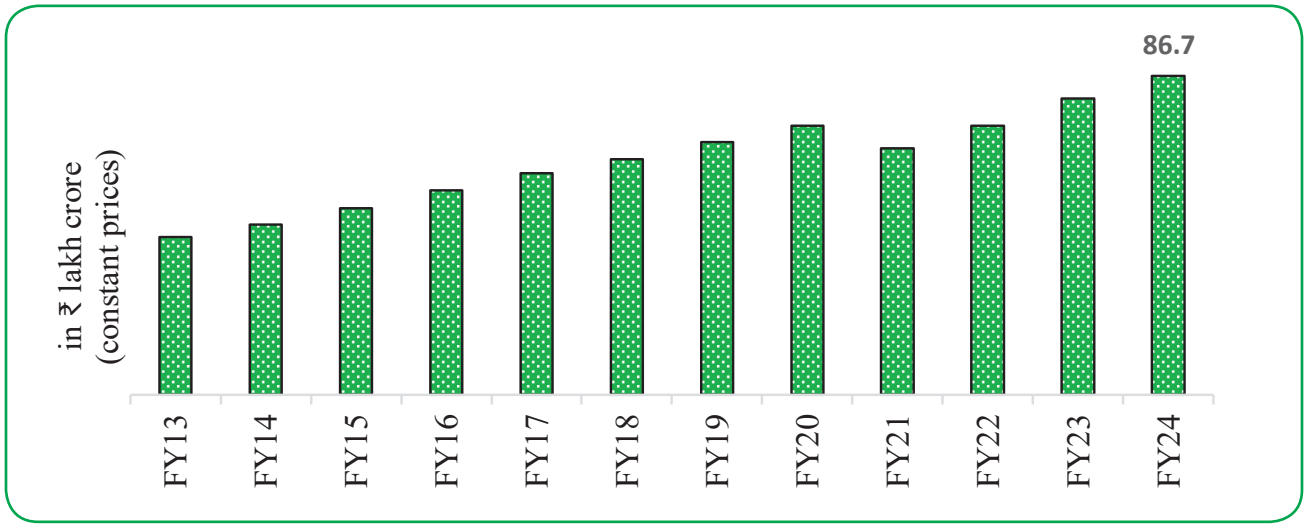

कोविड के बाद समग्र जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी

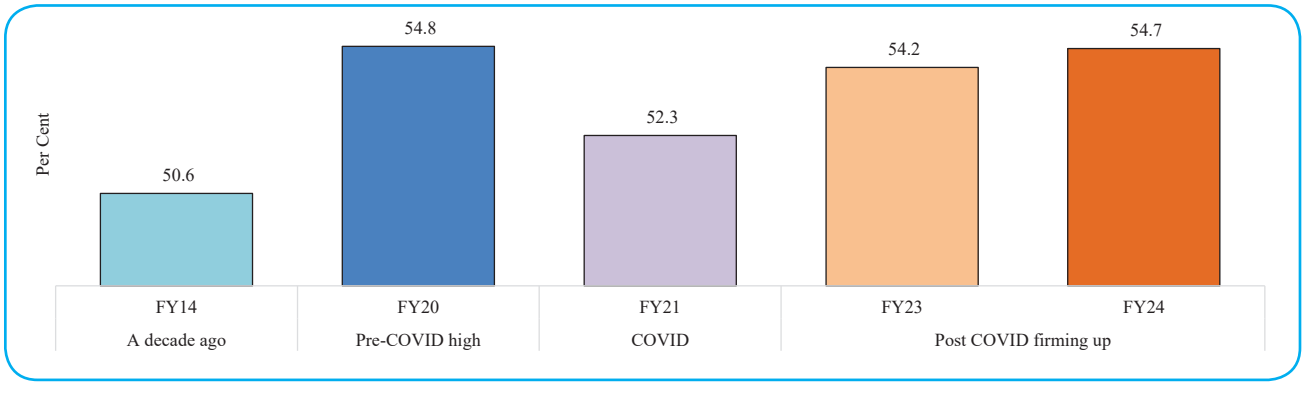

वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच वित्त वर्ष 24 में पीएमआई सेवाओं ने नई ऊंचाईयों को छुआ

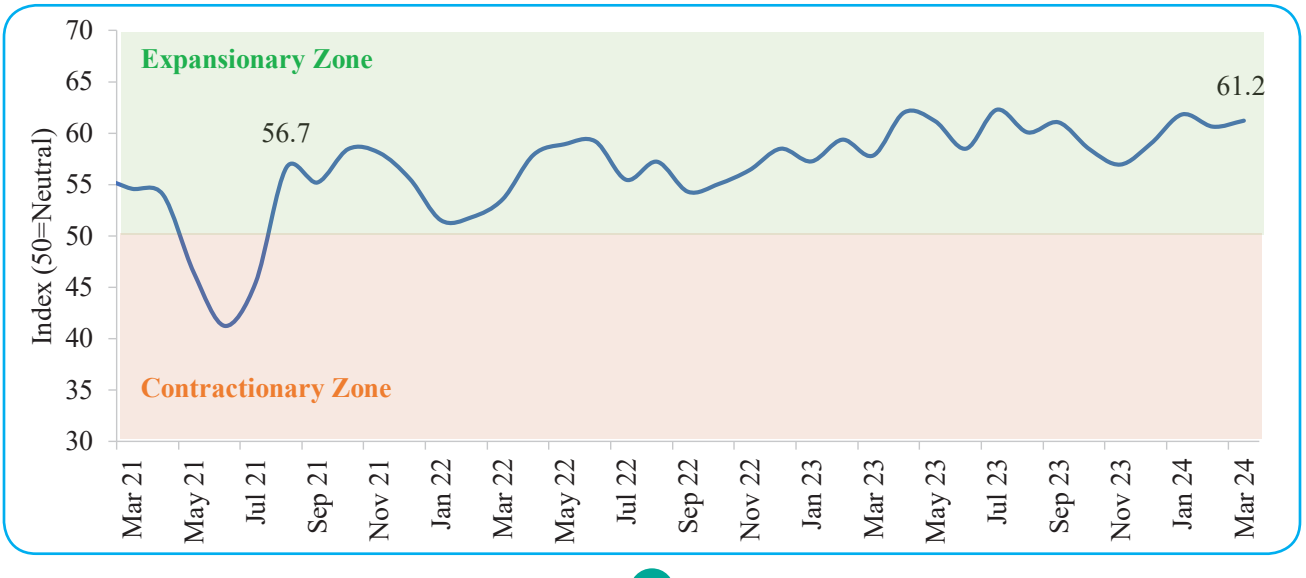

आवासीय अचल संपत्ति की बिक्री में तेजी

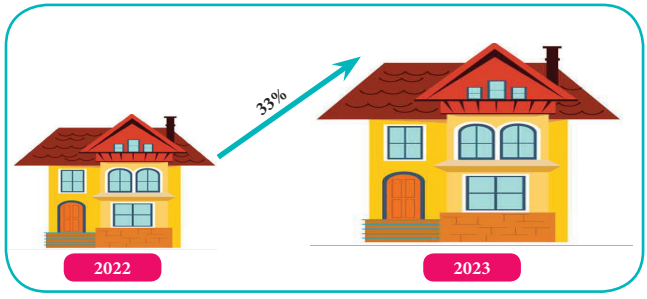

स्रोत: प्रॉपटाइगर

भारत में उभरते टेक स्टार्टअप

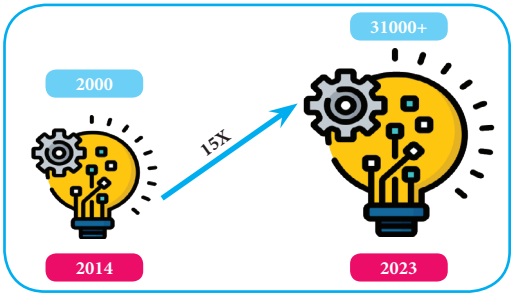

स्रोत: नैसकॉम और जिनोब (2023)। चुनौतियों का सामना-भारतीय टेक स्टार्ट-अप परिदृश्य रिपोर्ट 2023

आर्थक गतिविधि का समर्थन करने वाली भौतिक कनेक्टिविटी

रेलवे माल यातायात में निरंतर प्रगति

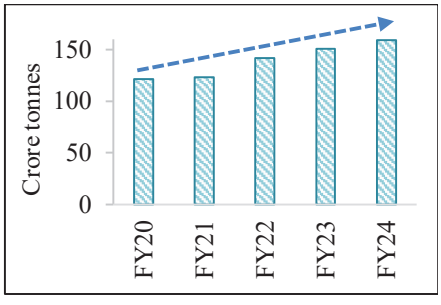

शिपिंग टन भार में निरंतर वृद्धि

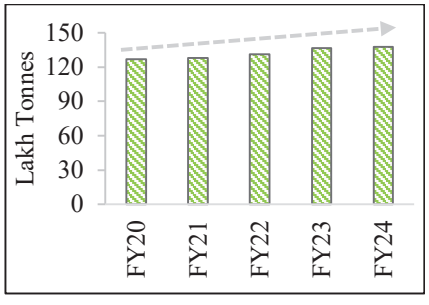

हवाई माल यातायात में वृद्धि

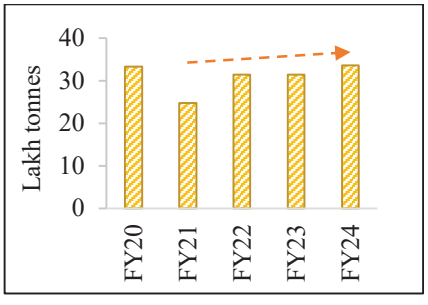

ओएनडीसी (डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क) का विकास मानचित्र

68 मिलियन लेन-देन शुरूआत से अब तक

85% छोटे विक्रेता

1200+ शहर

535,000+ विक्रेता

65 विक्रेता आवेदन

12 लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता

प्रति माह **9** मिलियन लेनदेन

22 क्रेता आवेदन

कृषि

- लगभग 57,00 किसान उत्पादक संगठन
- केवल वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में 23,000 से अधिक लेनदेन

खाद्य एवं पेय पदार्थ

- वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में ऑर्डरों में 18: की वृद्धि
- 347 शहरों में 95,000 रेस्तरां का नेटवर्क

फैशन और सौंदर्य

- वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 11% की वृद्धि
- 6400 से अधिक विक्रेता
- 900 शहरों में 15 लाख स्टॉक कीपिंग यूनिट्स (एसकेयू)

किराना

- वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 52% की वृद्धि
- 665 से अधिक शहरों में सेवारत 12,858 विक्रेताओं का नेटवर्क
- 6.3 मिलियन से अधिक एसकेयू

अवसंरचना : संभावित विकास को प्रोत्साहन

भौतिक संपर्क अवसंरचना

सड़क

- वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2024 के बीच राष्ट्रीय राज मार्ग निर्माण की औसत गति लगभग तीनगुना बढ़ गई।
- टोल डिजिटलीकरण से वर्ष 2014-24 के दौरान टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय लगभग 16 गुना कम हो गया।

रेलवे जल परिवहन

- वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 24 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई।
- नई लाइन, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण में महत्वपूर्ण निवेश।

नागरिक विमानन

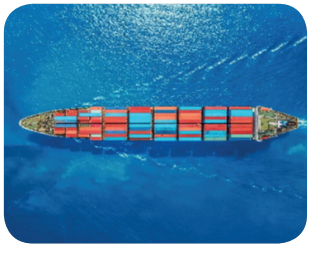

- लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंक 2014 में 44 से सुधर कर 2023 में 22 हो गई।
- सागरमाला के अंतर्गत 1.4 लाख करोड़ रुपये की लागत की 262 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

नागरिक उड्डयन

- वित्तवर्ष 24 में 21 हवाई अड्डों पर नये टर्मिनल भवन बनाये जायेंगे।
- प्रति वर्ष 62 मिलियन यात्रियों द्वारा यात्री प्रबंधन क्षमता में वृद्धि ।

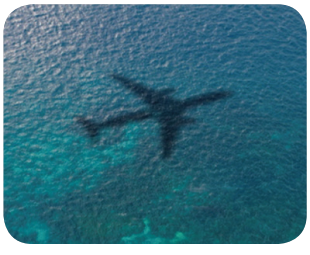

उर्जा

- भारत ने वर्ष 2030 तक गै. र-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50% संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- उजाला योजना के कारण वा. र्षिक ऊर्जा बचत 48.42 बि. लियन किलोवाट हुई और बि. जली बिलों में 19,335 करोड़ की वार्षिक बचत हुई।

बिजली

- मार्च 2024 के अंततक 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता स्थापित की जाएगी।
- स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2014 से 2023 के बीच 8.5 लाख करोड़ का नया निवेश हुआ।

नवीकरणीय ऊर्जा

शहरी क्षेत्र

- पीएमएवाई-यू: >1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई और 84 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा हो गया।
- अमृतमिशन: 83,327 करोड़ की लागत वाली 5,999 परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं। 51,434 करोड़ की लागत वाली 5,304 परियोजनाएँ पूरी हुईं।
- मेट्रोरेल/RRTS: 945 किलोमीटर चालू हैं। 27 शहरों में 939 किलोमीटर निर्माणाधीन हैं।वित्त वर्ष 24 में 86 किलोमीटर चालू हो गए।
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी: 63.07 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय इकाइयों का निर्माण किया गया। 6.37 लाख सामुदायिक और सार्व. जनिक शौचालय बनाए गए ।

सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना

खेल

- खेलो इंडिया: वित्त वर्ष 2014 में 38 नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई; जिसमें 58 पूर्ण हो गये।
- भारतीय खेल प्राधिकरण: वित्त वर्ष 24 में 9 बुनियादी ढांचा परियोजना ओं का मंजूरी दी गई। जिसमें 13 पूरी हुई।

जल एवं स्वच्छता

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण:. वित्त वर्ष 2014 में, 6,802. 6 करोड़ का उपयोग किया गया।
- जलजीवन मिशन: अब तक 14.89 करोड़ से अधिक ग्र. ामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया।

जल संसाधन प्रबंधन

- नमामिगंगे: सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए हाइब्रिड वा. र्षिकी मॉडल अपनाया गया; 33 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम: 2016-24 के दौरान 25.80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया गया।

पर्यटन

- पीआरएएसएडी (प्रसाद) योजना: 29 नये तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई।
- स्वदेश दर्शन 2.0: 3,800 करोड़ का परिव्यय।

अन्तरिक्ष

अंतरिक्ष संपत्ति

भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ हैं, जिनमें 18 संचार उपग्रह, 9 नेविगेशन उपग्रह, 5 वैज्ञानिक उपग्रह, 3 मौसम संबंधी उपग्रह और 20 पृथ्वी अवलो. कन उपग्रह शामिल हैं।

डिजिटल

दूरसंचार आईटी

- जून 2024 तक 8.02 लाख मोबाइल टावर होंगे।
- 29.37 लाख बेसट्रां सीवर स्टेशन (बी. टीएस) और 4.5 लाख 5 जीबीटीएस होंगे।
- भारत ने परियोजना: 6,85,501 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाई गई। 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को ओएफसी से जोड़ा गया।

इलकट्रोनिकी और आईटी

- व्यापक भारत एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ स्वीकृत।
- एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत ने जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में घोषित शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75 वां स्थान हासिल किया।
- डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म 26.28 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता ओंतक पहुंच चुका है।

जलवायु परिवर्तन और भारतः हमें इस समस्या को अपने नजरिए से क्यों देखना चाहिए

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दे

मूल मुद्दे, यानी अति उपभोग, का समाधान करने की कोशिश नहीं करता

नये युग के संसाधनों की अतार्किक खोज ग्रह को नुकसान पहुंचा रही है।

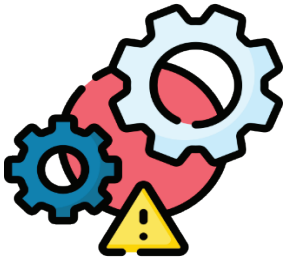

वर्तमान उपाय जल वायु परिवर्तन से निपटने में असफल हो सकते हैं।

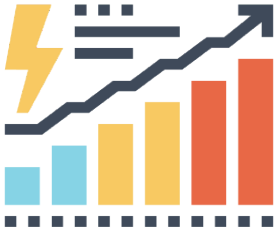

ऊर्जा की खपत करने वाली एआई केलिए 'होड़' जलवायुल क्ष्योंके सीधे विपरीत है।

पश्चिम में खाद्य-आहार संतुलन खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि मानव उपभोग की तुलना में पशुओं के उपभोग के लिए अधिक अनाज का उत्पादन किया जाता है।

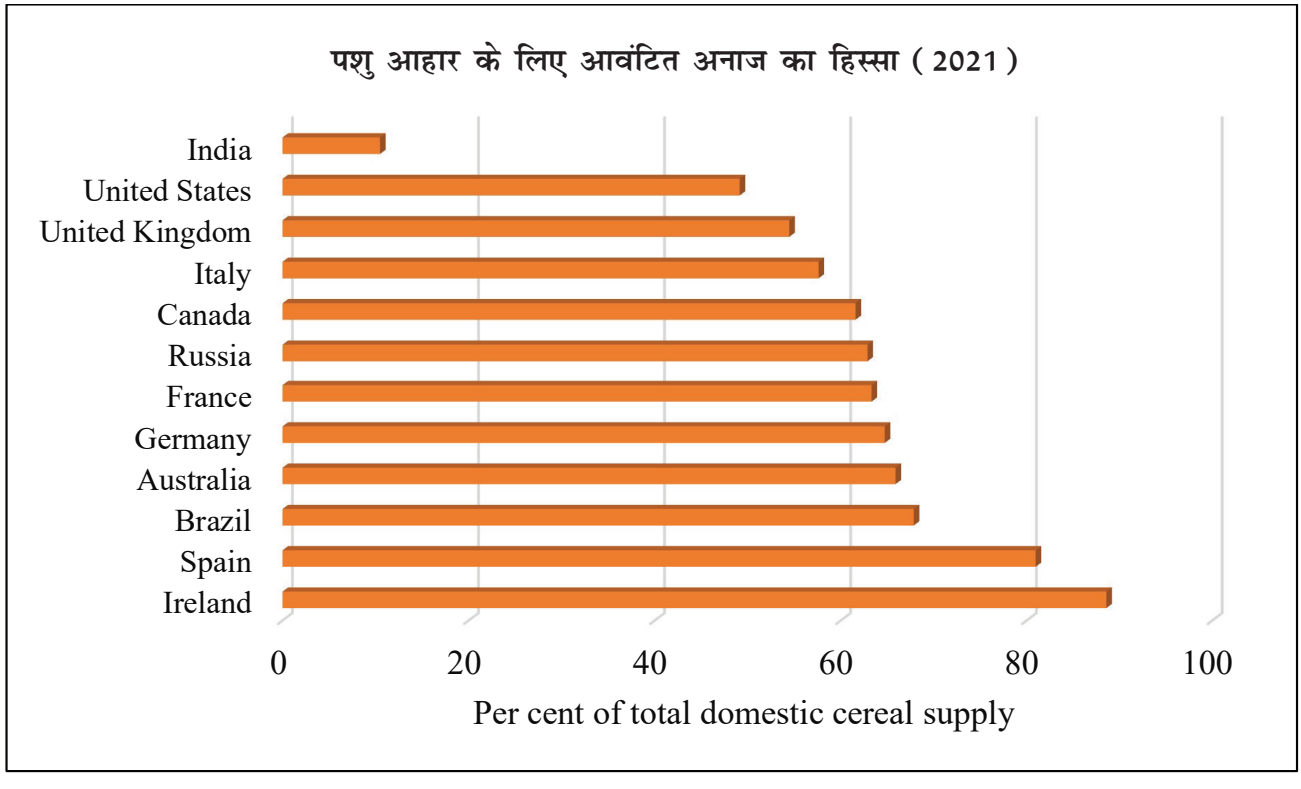

स्रोतः संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (2023)।

अधिकांश विकसित देशों में घरेलू अनाज उत्पादन का एक तिहाई से भी कम हिस्सा मानव उपभोग के लिए होता है

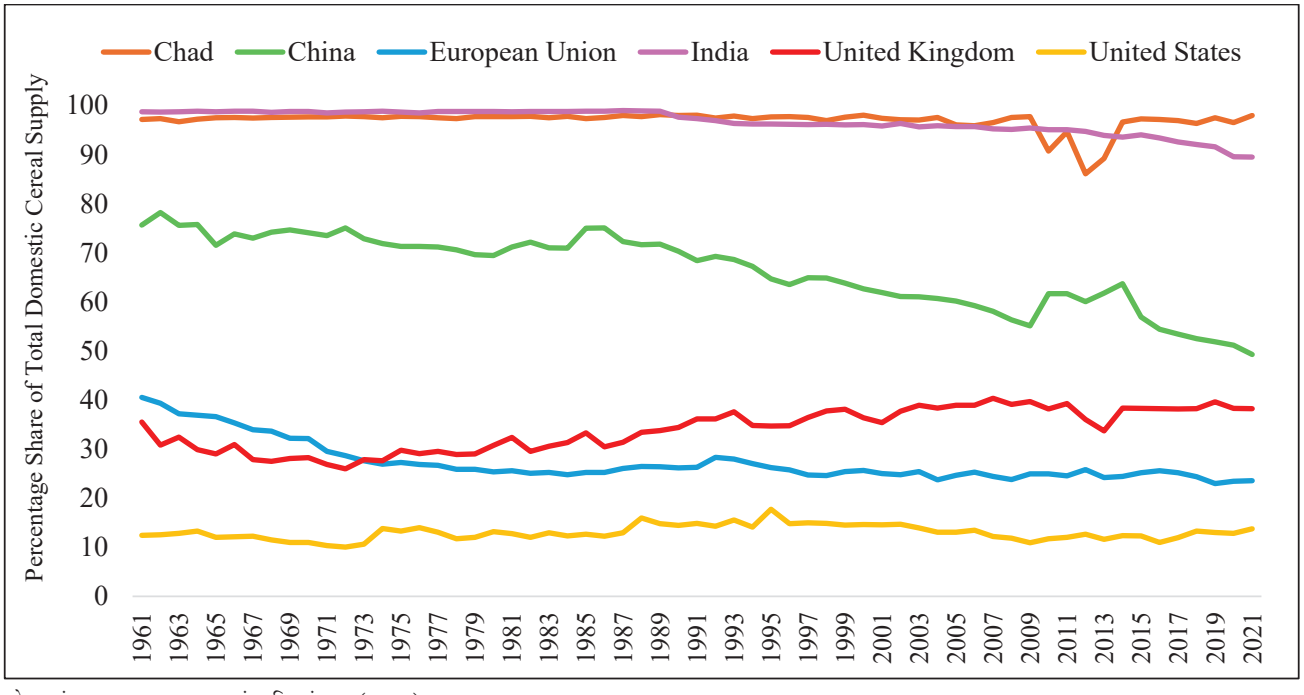

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (2023)

पौधे-आधारित विकल्पों की तुलना में 1000 किलो कैलोरी मांस का उत्पादन करने के लिए लगभग 100 गुना अधिक भूमि की आवश्यकता होती है।

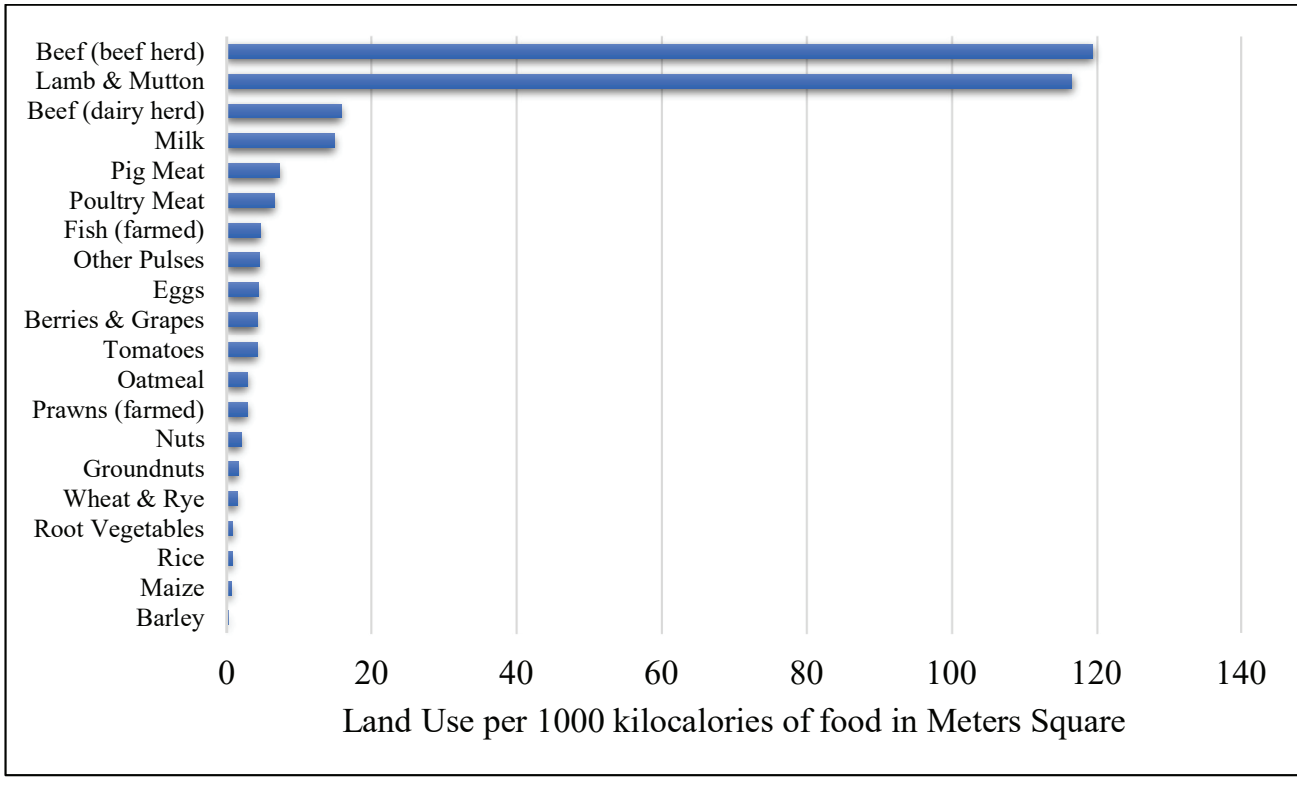

स्रोत: जोसेफपूअरे और थॉमस नेमेसेक (2018)। आवर वर्ल्डइन डेटा द्वारा अतिरिक्त गणना

संधारणीय आवास का मार्ग

पारंपरिक भारतीय रहने की जगहों पर वापसी:

- अच्छी तरह हवादार स्थानों के साथ केंद्रीय आंगन।
- प्राकृतिक रोशनी और ठंडक के रास्ते।
- स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग
- स्थानीय श्रमिक निर्माण कार्य में सहायता कर रहे हैं।

संधारणीय आवास का मार्ग

हमारी परंपरा के अनुसार बहु-पीढ़ी वाले परिवारों की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करना:

- आज के एकल परिवार हमा. रे पुराने सामाजिक मानदंडों से अलग हैं।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भी बहु-पीढ़ी वाले घरों में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के महत्व को पहचानता है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारतीय दृष्टिकोण

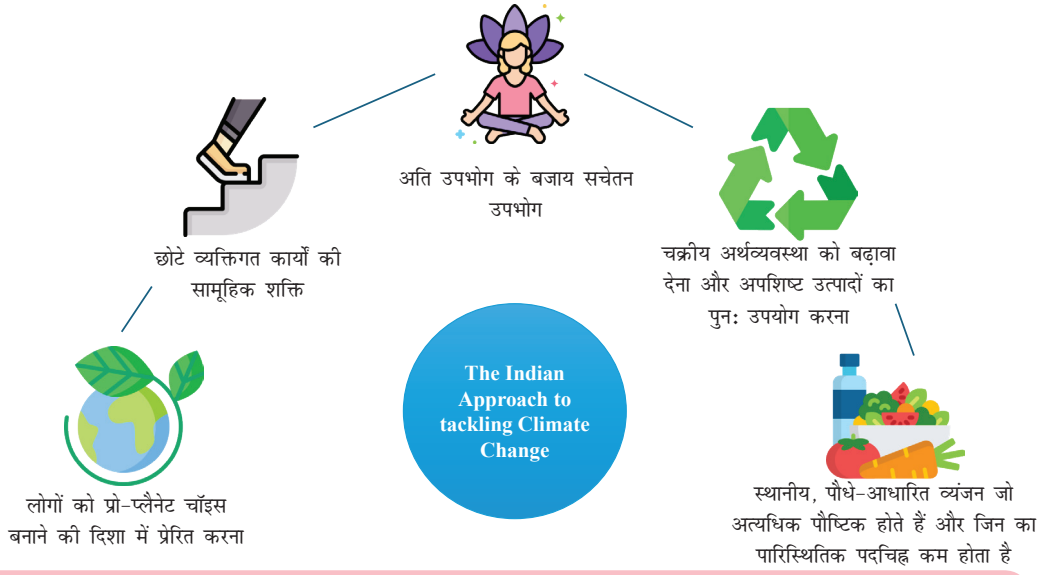

मिशन लाइफ प्रकृति के अनुरूप स्वाभाविक रूप से टिकाऊ जीवन शैली का प्रस्ताव करता है

सत्यमेव जयते
Government of India

आर्थिक कार्य विभाग
DEPARTMENT OF
ECONOMIC AFFAIRS